

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8> डायल-1 1 2 सेवा का विस्तार...



निर्णायक दौर में पहुंचे भारत इटली संबंध : पीएम मोदी

मोदी ने इटली की पीएम मेलोनी को दी मेलोडी टॉफी - कूटनीति में घुली मिठास

रोम। प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंचने पर भारत और इटली के संबंधों को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल देखने को मिली। रोम पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मेलोनी से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने रात्रिभोज के बाद रोम के ऐतिहासिक कोलोसियम का दौरा करते हुए विभिन्न वैश्विक तथा द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि रोम पहुंचने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात्रिभोज और ऐतिहासिक कोलोसियम भ्रमण का अवसर मिला। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने अनेक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया तथा भारत और इटली की मित्रता को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री मेलोनी ने भी मोदी के स्वागत में लिखा, रोम में स्वागत है मेरे मित्र। कोलोसियम में दोनों नेताओं की अनौपचारिक बातचीत और रोम की

सड़कों पर साथ यात्रा करते दृश्य ने भारत और इटली के बीच बढ़ती निकटता को दर्शाया। इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच नई कार कूटनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियामपाओलो टोमासेती की भारतीय संस्कृति और वाराणसी से प्रेरित चित्रकृतियों की भी सराहना की। टोमासेती चार दशकों से भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े रहे हैं। रोम पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने भी प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। होटल के बाहर भारतीय प्रवासियों ने तिरंगे लहराए, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं और प्रधानमंत्री के समर्थन में नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों से मुलाकात की, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया तथा एक बाल प्रशंसक को हस्ताक्षरित चित्र भी भेंट किया। उन्होंने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि इटली में रहने वाले भारतीय भारत और इटली के



संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हम आपको यह भी बता दें कि मोदी और मेलोनी ने संयुक्त रूप से एक लेख भी लिखा है, जिसमें भारत और इटली के संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के नए दौर में प्रवेश करने वाला बताया गया है। दोनों नेताओं ने

कहा कि दोनों देशों के संबंध अब केवल मित्रता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र और साझा भविष्य की सोच पर आधारित व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। लेख में कहा गया कि तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और इटली आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो से आगे ले जाने का लक्ष्य रखा है। रक्षा, एयरोस्पेस, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, मशीनरी, दवाइयां, वस्त्र, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि मेड इन इटली और मेक इन इंडिया पहल के बीच स्वाभाविक तालमेल दोनों देशों की औद्योगिक क्षमताओं को नई दिशा देगा। इटली की डिजाइन और विनिर्माण क्षमता को भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, इंजीनियरिंग प्रतिभा और नवाचार आधारित उद्यमिता से जोड़ने पर जोर दिया गया।



राजनीतिक मतभेद भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा के आड़े नहीं आने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी राजनीतिक सोच अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रहित सबसे ऊपर होना चाहिए।

शरद पवार, एनसीपी एसपी प्रमुख

साल की उम्र में वे बारामती से पुणे आए थे, क्योंकि उस समय उनके गृह नगर में कॉलेज नहीं था। बाद में वे पुणे शहर यूथ कांग्रेस और फिर महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के प्रमुख बने। पवार ने

एक घटना को साझा करते हुए कहा कि दिल्ली स्थित तीन मूर्ति भवन में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात उनके जीवन के यादगार पलों में शामिल है।

शरद पवार ने पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़े प्रसंग किए साझा:

उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछने के लिए किसानों और युवाओं से जुड़े कई सवाल तैयार किए थे, लेकिन नेहरू के प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने वे सब कुछ भूल गए। पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़ा एक प्रसंग भी सुनाया। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ की यात्रा के दौरान इंदिरा गांधी ने भारतीय प्रधानमंत्री को पर्याप्त सम्मान नहीं मिलने पर नाराजगी जताई थी। पवार ने कहा कि इंदिरा गांधी ने सोवियत अधिकारियों से कहा था, मैं 40 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती हूँ। यदि उनके सम्मान का आदर नहीं होगा। तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। 1% कार्यक्रम के अंत में पवार ने विभिन्न दलों के पुराने सहयोगियों के एक मंच पर आने का स्वागत किया और राष्ट्रीय हित में मिलकर काम करने का आह्वान किया।

राहु बन राजनीति का वातावरण दूषित कर रहे राहुल गांधी: नितिन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भाजपा नेताओं ने करारा पलटवार किया है।

नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता के बयान की कड़ी निंदा की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह राहुल गांधी की अराजकतावादी और हहशा मानसिकता को दर्शाता है। नितिन नवीन ने राहुल गांधी की राहु की संज्ञा देते हुए कटाक्ष किया है कि वह भारतीय राजनीति के वातावरण को गंदा और दूषित कर रहे हैं। इसी तरह तीखे प्रहार के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल के इतने हल्के शब्द उनकी परवरिश पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष

उन्होंने बयान पर सवाल उठाया कि क्या नक्सलवाद को समाप्त करना गद्दारी है? क्या देश की जमीन को सुरक्षित रखना गद्दारी है? क्या पूरे विश्व में भारत के तिरों का सम्मान बढ़ाना गद्दारी है? आने वाले समय में राहुल गांधी और कांग्रेस को अपने दुर्भाग्यपूर्ण बयानों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।

विजय कैबिनेट में शामिल होगी कांग्रेस

59 साल बाद तमिलनाडु की सत्ता में बनेगी भागीदार

नई दिल्ली। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भले ही कमजोर रहा हो मगर करीब छह दशक के लंबे अंतराल के बाद पार्टी राज्य में सत्ता की भागीदार बनने जा रही है। कांग्रेस के दो विधायक गुरुवार को मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक संग गठबंधन में उतरी कांग्रेस ने बहुमत से पीछे रहे विजय के मुख्यमंत्री बनने की राह बनाने में अहम भूमिका निभाई। द्रविड़ राजनीति के वचर्चवाले तमिलनाडु में कांग्रेस के दो सदस्यों



का मंत्री बनना इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि वस्तुतः छह दशक बाद कोई राष्ट्रीय पार्टी राज्य की सत्ता में भागीदारी बन रही है।

दो विधायक बनेंगे मंत्री

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राज्य में पार्टी के दो विधायकों के मंत्री बनने की जानकारी एक्स पोस्ट पर साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विधायक एडवोकेट राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन को तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल करने की मंजूरी दे दी है और गुरुवार को दोनों मंत्री पद की शपथ लेंगे।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने राज्य में पार्टी के दो विधायकों के मंत्री बनने की जानकारी एक्स पोस्ट पर साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने विधायक एडवोकेट राजेश कुमार और पी. विश्वनाथन को तमिलनाडु कैबिनेट में शामिल करने की मंजूरी दे दी है और गुरुवार को दोनों मंत्री पद की शपथ लेंगे।



रायपुर। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और कुपोषण मुक्ति को एक साथ जोड़ते हुए राज्य सरकार ने एक ऐसी पहल शुरू की है, जिसने ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आशा, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिरता की नई रोशनी जगाई है। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण आहार के निर्माण एवं वितरण का दायित्व महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपकर सरकार ने महिलाओं को केवल रोजगार ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें विकास की मुख्यधारा में सशक्त भागीदारी का अवसर भी प्रदान किया है।

मायावती ने कांग्रेस नेताओं से मिलने को किया इनकार

लखनऊ। बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेताओं ने मायावती से मिलने का प्रयास किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख द्वारा कथित तौर पर मिलने से इनकार करने के बाद उन्हें बिना मुलाकात के ही लौटना पड़ा। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम और सांसद तनुज पुनिया मायावती के आवास पर पहुंचे और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। खबरों के मुताबिक, सुरक्षाकर्मियों ने बसपा प्रमुख को अपना संदेश पहुंचाया, लेकिन मायावती ने मुलाकात से इनकार कर दिया। राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही थीं कि राहुल गांधी के प्रस्तावित दौर से पहले कांग्रेस नेता मायावती से कुछ राजनीतिक मामलों पर चर्चा करना चाहते थे। हालांकि, अंततः यह मुलाकात नहीं हो सकी। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए तनुज पुनिया ने कहा कि कांग्रेस कार्यालय से निकलने के बाद वह और राजेंद्र पाल गौतम मायावती के आवास पर उनका हालचाल जानने गए थे।



उत्तर बंगाल को सीएम सुर्वेदु अधिकारी की सौगात

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुर्वेदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि उत्तर बंगाल ने लगातार भाजपा का समर्थन किया है और उन्होंने पार्टी के घोषणापत्र के वादों को दोहराया, जिनमें इस क्षेत्र में एम्स, आईआईटी और कैंसर अस्पताल की स्थापना शामिल है। पश्चिम बंगाल के सीएम सुर्वेदु अधिकारी शपथ ग्रहण के बाद पहली बार उत्तर बंगाल पहुंचे और कहा कि उनकी सरकार विकास योजनाओं की नियमित निगरानी और लोगों से बातचीत के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काम करेगी। बागडोगरा हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, उत्तर बंगाल ने बार-बार भाजपा का साथ दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के हाथों को मजबूत किया है। उत्तर बंगाल में काम करके हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि इस क्षेत्र के भाजपा मंत्री नागरिकों से सीधे जुड़ने के लिए साप्ताहिक जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित करेंगे।



ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर जयराम रमेश का हमला

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को केंद्र सरकार पर ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के आलोचकों को चीन के प्रति नरम बताने के लिए प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार स्वयं चीन के सामने निरंतर, सुनियोजित आत्मसमर्पण की नीति अपना रही है। एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में रमेश ने कहा कि सरकार इस परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय और मानवीय मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने अब अपने ही माध्यम से एक प्रचार अभियान शुरू किया है, जिसमें ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को लेकर निर्मित सभी लोगों को चीन के प्रति नरम बताया जा रहा है। यह पाखंड की पराकाष्ठा है, खासकर ऐसी सरकार की ओर से जो खुद चीन के सामने निरंतर, सुनियोजित आत्मसमर्पण की नीति का पालन करती है।



केरल सरकार ने एलडीएफ का के-रेल प्रोजेक्ट को किया रद्द

तिरुवनंतपुरम। केरल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल ने विवादास्पद तिरुवनंतपुरम-कासरगोड सिल्वरलाइन रेल कॉरिडोर परियोजना को रद्द करने का निर्णय लिया है, जिसे पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार ने शुरू किया था। एक महत्वाकांक्षी अवसंरचना परियोजना के रूप में प्रचारित इस परियोजना को जनता के व्यापक विरोध का सामना करना पड़ा था। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वीडी सतीशन ने कहा कि सरकार ने राजस्व विभाग को भूमि सीमांकन के लिए लगाए गए सभी सर्वेक्षण पत्थरों को हटाने का निर्देश दिया है और परियोजना के लिए शुरू की गई सभी भूमि अधिग्रहण कार्यवाही रद्द कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि मामलों की प्रकृति की समीक्षा करने के बाद सरकार ने राज्य भर में परियोजना के विरोध प्रदर्शनों से संबंधित मामलों को वापस लेने के लिए अदालतों में हलफनामे दाखिल करने का निर्णय लिया है।



प्रमुख समाचार

सच के आईने से डरती है मोदी सरकार : पवन खेड़ा

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सच का सामना करने से डरती है और पिछले 12 वर्षों में उसने लोकतंत्र का आईना माने जाने वाले विपक्ष तथा मीडिया की आवाज को दबाने का काम किया है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री मोदी देश में आर्थिक संकट के लिए वैश्विक युद्धों को जिम्मेदार ठहराते हैं लेकिन सच यह है कि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही थी और कांग्रेस लगातार इसकी चेतावनी देती रही है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में विपक्ष और मीडिया वह आईना होते हैं, जो सत्ता को सच्चाई दिखाते हैं, लेकिन सच से डरने वाली मोदी सरकार इस आईने को तोड़ने का काम कर रही है। झूठ आईने से डरता है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने पिछले 12 वर्षों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि उन्हें डर है कि मीडिया उनसे कठिन सवाल पूछ सकता है।



इटली और भारत के बीच के रिश्तों में अभूतपूर्व विस्तार

नरेंद्र मोदी /जॉर्जिया मेलोनी

भारत और इटली के संबंध अब एक निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में अभूतपूर्व तेजी से विस्तार हुआ है। यह संबंध केवल सौहार्दपूर्ण मित्रता तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब स्वतंत्रता और लोकतंत्र के मूल्यों तथा भविष्य के साझा दृष्टिकोण पर आधारित एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। ऐसे समय में, जब पूरी दुनिया की व्यवस्था बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, इटली और भारत की साझेदारी उच्च राजनीतिक और संस्थागत स्तर पर लगातार संवाद से आगे बढ़ रही है। यह संबंध अब एक नए और अधिक

व्यापक स्तर पर पहुंच रहा है, जिसमें दोनों देशों की आर्थिक ताकत, सामाजिक रचनात्मकता और हजारों वर्षों पुरानी सभ्यतागत विरासत शामिल है। हमारा सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा इस बात पर निर्भर करेगी कि देश कितनी क्षमता से नवाचार करें, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करें और अपनी रणनीतिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करें। इसी उद्देश्य से हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा तथा विविध बनाने का संकल्प लिया है, ताकि नए लक्ष्यों को हासिल किया जा सके और दोनों देशों की पूरक शक्तियों का बेहतर उपयोग हो सके। यह

केवल दो व्यवस्थाओं का साधारण मेल नहीं है, बल्कि ऐसा साझा मूल्य निर्माण है जिसमें दोनों देशों की औद्योगिक ताकतें एक-दूसरे को और अधिक मजबूत बनाती हैं। यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश बढ़ाने का रास्ता खोलता है। हमारा लक्ष्य 2029 तक भारत और इटली के बीच व्यापार को 20 अरब यूरो से आगे ले जाना है। इसमें रक्षा एवं एयरोस्पेस, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, मशीनरी, ऑटोमोबाइल पुर्जें, रसायन, दवाइयां, वस्त्र, कृषि-



खाद्य क्षेत्र और पर्यटन समेत कई क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहेगा। 'मेड इन इटली' हमेशा से दुनिया भर में उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है, और आज इसका स्वाभाविक तालमेल 'मेक इन इंडिया' पहल के उच्च गुणवत्ता वाले लक्ष्यों के साथ

दिखाई देता है। तकनीकी नवाचार हमारी साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। आने वाले दशकों में दुनिया एक बड़े तकनीकी बदलाव के दौर से गुजरेगी, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्वांटम कम्प्यूटिंग, उन्नत विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिज और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में तेज प्रगति होगी। भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता - इन क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक बनाती है। दोनों देशों के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के

बीच बढ़ती साझेदारी भी इसे मजबूती देगी। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) पहले से ही दुनिया के कई देशों, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों, के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आज हमारे समाज और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल रही है। इटली और भारत लंबे समय से इस विकास जिम्मेदार और मानव-केंद्रित हो। भारत और इटली एआई-को समावेशी विकास का एक शक्तिशाली माध्यम भी मानते हैं, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के लिए। डिजिटल

पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और आसान, बहुभाषी तकनीकों के जरिये एआई सामाजिक और डिजिटल खाइयों को कम कर सकता है। हमारा दृष्टिकोण भारत की विशाल डिजिटल क्षमता को इटली की नैतिक और औद्योगिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ना है, ताकि तकनीक मानव गरिमा की सेवा कर सके। सुरक्षित डिजिटल सहयोग, क्षमता निर्माण और मजबूत साइबर ढांचे से जुड़ी श्रेष्ठ कार्यपालिकाओं को साझा करके, हम एक ऐसा खुला, भरोसेमंद और समान डिजिटल वातावरण बनाना चाहते हैं, जिसमें हर देश एआई का उपयोग कर सके और उससे लाभ उठा सके।

हाईकोर्ट ने रद्द किया हसदेव नदी में प्रस्तावित रेत खदान का टेंडर

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने जांजगीर-चांपा जिले की हसदेव नदी में प्रस्तावित रेत खदान के टेंडर को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बिना फाइनल जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के रेत खदानों की नीलामी नहीं की जा सकती। ग्राम पंचायत हथनेवरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर टेंडर जारी करना नियमों के खिलाफ है। मामला जांजगीर-चाम्पा जिले के ग्राम पंचायत हथनेवरा का है, जहां प्रशासन ने रेत खनन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की थी। आरोप था कि यह प्रक्रिया पांच साल पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई, जिसकी वैधता समाप्त हो चुकी थी।

इसके बावजूद 30 मार्च को रेत नीलामी का टेंडर जारी किया गया और सफल बोलीदाता का

ग्राम पंचायत सरपंच ने दायर की थी याचिका



चयन भी कर लिया गया। हथनेवरा के सरपंच ने इस टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई। पंचायत की दलील थी कि जिले

में कोई वैध और स्वीकृत नई छ्स्क रिपोर्ट मौजूद नहीं है, इसलिए टेंडर प्रक्रिया अवैध है।

मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार

अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट वेबसाइट पर अपलोड कर देना पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट पर जनता

से आपत्तियां आमंत्रित करना जरूरी है। उसके बाद कलेक्टर की मंजूरी आवश्यक है। तभी उसे अंतिम जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट माना जाएगा।

इधर राज्य सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि 2025 की नई रिपोर्ट तैयार कर 27 नवंबर 2025 को ऑनलाइन अपलोड की गई थी और टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी। ऐसे में रोक लगाने से सरकारी राजस्व का नुकसान होगा। मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि सरकार जिस रिपोर्ट का हवाला दे रही थी, वह केवल ड्राफ्ट रिपोर्ट थी, जिसे अंतिम मंजूरी नहीं मिली थी।

हाईकोर्ट ने टेंडर रद्द करते हुए राज्य सरकार को यह छूट दी कि वह नियमों के तहत नई और स्वीकृत छ्स्करिपोर्ट तैयार कराकर दोबारा टेंडर जारी कर सकती है।

धनवार नाके पर किसानों का प्रदर्शन



■ जमीन अधिग्रहण के बाद अब तक मुआवजे नहीं मिलने पर जताया विरोध

बलरामपुर। जिले के वाइफनगर स्थित धनवार अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर किसानों ने जमीन अधिग्रहण के बाद अब तक मुआवजा नहीं मिलने के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जल्द मुआवजा भुगतान की मांग की। जानकारी के

अनुसार, धनवार अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट निर्माण के लिए प्रशासन द्वारा करीब 20 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। किसानों का आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के वर्षों बाद भी उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला, जिससे वे आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। प्रदर्शन के

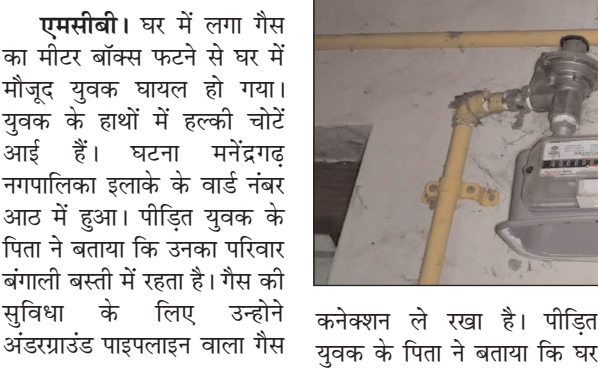
ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज देशभर के मेडिकल स्टोर बंद



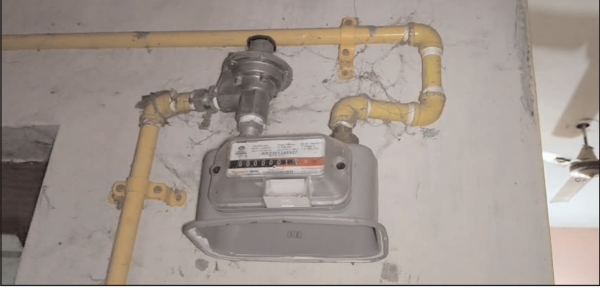
जगदलपुर। ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री और भारी दवािकाउंट के विरोध में देशभर के मेडिकल स्टोर संचालकों ने 20 मई को हड़ताल करने का फैसला किया है। हड़ताल का आह्वान ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट और रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर एंड केमिस्ट अलायंस (आरडीसीए) ने किया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में मेडिकल स्टोर संचालकों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ में इस बंद का असर देखने को मिल रहा है। जगदलपुर में मेडकल स्टोर बंद नजर आए। दिल्ली जोनल हेड डॉ. बसंत गोयल ने बताया कि ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ कई वर्षों से सरकार से शिकायत की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए दवाइयों की बिक्री नियमों के खिलाफ है और इससे छोटे

मेडिकल स्टोर कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है।गोयल ने बताया कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के अनुसार दवाई केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर और लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर से फार्मासिस्ट द्वारा ही दी जा सकती है। बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाई देना कानूनन गलत है। इसके बावजूद कई ऑनलाइन कंपनियां नियमों का उल्लंघन कर दवाइयों की डििलीवरी कर रही हैं। मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि पहले लोग सीधे मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने आते थे, लेकिन अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने सरकार से ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स बुधवार को देशभर में मेडिकल स्टोर बंद रखने का आह्वान किया है।

मनेंद्रगढ़ में गैस का मीटर फटने से युवक घायल, हादसे से दहशत में कॉलोनी के लोग



कनेक्शन ले रखा है। पीड़ित युवक के पिता ने बताया कि घर



में गैस की गंध फैल रही थी। उनका बेटा गैस की गंध को चेक

कर रहा था, तभी घर के भीतर दीवार पर लगा मीटर बॉक्स धमाके के साथ फट गया। गनीमत रही की हादसे में युवक को कोई गंभीर चोटें नहीं आईं।

हादसे के बाद पूरे मोहल्ले में दशहत का माहौल है। कई लोगों ने पाइपलाइन वाला गैस कनेक्शन ले रखा है। आस पास रहने वाले लोगों ने भी बताया कि धमाका काफी तेज था। परिवार वालों ने

बताया कि मीटर बॉक्स फटने के बाद आग नहीं लगी इस बात शुक्र है, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद स्थानीय लोगों में पाइपलाइन से आ रही गैस व्यवस्था की सुरक्षा को लेकर भारी चिंता है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के कई घंटे बाद तक कंपनी की कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं आया।

पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना की सूचना देने के लिए दिए गये टोल फ्री नंबर पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन नंबर नहीं लग पाया। इस बात को लेकर भी लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने पाइपलाइन से गैस कनेक्शन तो ले लिया लेकिन हादसा होने पर उनकी शिकायत तक सुनने को कोई तैयार नहीं है।

बीएसपी कर्मचारी से 38 लाख की हुई टगी

भिलाई। पुलिस और सरकार लगातार लोगों के बीच जन जागरुकता अभियान चलाती रहती है। अभियान के तहत लोगों को फ्रॉड करने वालों से सावधान रखने की हिदायत दी जाती है। आरबीआई के जरिए भी लोगों को निवेश के नाम पर टगी से बचने की सलाह दी जाती है। बावजूद इसके लोग टगों के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी की गाढ़ी और बड़ी कमाई गंवा देते हैं। भिलाई में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां भिलाई स्टील प्लांट के एक कर्मचारी से एकमुश्त निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा देकर, 38 l30 लाख की धोखाधड़ी कर ली गई है। भट्टी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर पिता और उसके दो बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर



जांच शुरू कर दी है। आरोपी है कि तीनों मिलकर टगी की रैकेट चला रहे हैं। भट्टी पुलिस के मुताबिक पीड़ित संतोष कुमार, उम्र 57 साल भिलाई के सेक्टर चार के रहने वाले हैं। संतोष भिलाई बीएसपी में इलेक्ट्रिशियन के पद पर कार्यरत हैं। साल 2022 में अपनी मैच्योर पॉलिसी बंद कराने के लिए वो सिविक सेंटर स्थित बीमा कार्यालय गए थे। कम पड़े-लिखे होने के कारण उन्हें फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात सेक्टर-6 निवासी के।

देवासहायम से हुई, जिसने मदद के बहाने उनसे नजदीकियां बढ़ा ली। आरोप है कि 28 सितंबर 2022 को देवासहायम अपने दो बेटों, के। रवि कुमार और के। राजेश कुमार के साथ संतोष के घर पहुंचा। तीनों ने निवेश करने के नाम पर मोटी रकम रिटर्न में देने का दावा किया। जिसके झांसे में आकर पीड़ित ने पहले 14 लाख का चेक दे दिया। बाद में परिवार के अन्य सदस्यों के बीमा के नाम पर 17 l30 लाख और ऐंट लिए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने सिविक सेंटर सुपर बाजार से करीब 7 लाख के इलेक्ट्रॉनिक सामान (फ्रीज, एसी, टीवी, मोबाइल आदि) भी पीड़ित से खरीदवा लिए, जिन्हें बाजार में बेचकर पैसे लौटाने का वादा किया गया था।

संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी में नियमों की अनदेखी का आरोप



सरगुजा। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। छात्र नेता हिमांशू जायसवाल ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। हिमांशू जायसवाल का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ सरकार के रोस्टर नियमों का पालन नहीं

किया गया। साथ ही नई कार्यपरिषद की मंजूरी से पहले ही भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ उम्मीदवारों के नाम पहले से तय हैं और इंटरव्यू चैनल तक की जानकारी पहले ही बाहर आ चुकी है। हालांकि कुलपति ने आरोपों को खारिज किया है। यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के कुल 26

पदों पर नियमित भर्ती होनी है। छात्र नेता का आरोप है कि इतनी बड़ी भर्ती प्रक्रिया में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। उनका कहना है कि अप्रैल में नई कार्यपरिषद बनी, लेकिन भर्ती का विज्ञापन मार्च में ही निकाल दिया गया। यानी कार्यपरिषद की मंजूरी के बिना प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

हिमांशू जायसवाल ने कहा कि आरटीआई से मिली जानकारी में यूनिवर्सिटी ने खुद माना है कि भर्ती के लिए कोई रोस्टर समिति गठित नहीं की गई और रोस्टर पंजी भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि दावा-आपत्ति के निराकरण की जानकारी भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई। यूनिवर्सिटी इसे सार्वजनिक करने से बच रही है।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

लाखागढ़ में कराए गए कार्य वसूली योग्य नहीं पाई गई राशि

महासमुंद। जनपद पंचायत पिथौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत लाखागढ़ में सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक के विरुद्ध आर्थिक अनियमितता तथा फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासकीय राशि गबन किए जाने संबंधी शिकायत की जांच में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पिथौरा को मामले की जांच हेतु तीन सदस्यीय जांच दल गठित करने कहा गया था। जांच दल में सहायक लेखा परीक्षक दिनेश कुमार दीक्षित, सहायक विकास विस्तार अधिकारी श्री लोकेश तथा तकनीकी सहायक मनरेगा त्रिलोकीनाथ सिन्हा शामिल थे। शिकायत में गौठान एवं गोधन न्याय योजना के कार्यों में लापरवाही का उल्लेख करते हुए मनरेगा कार्य में बिना कार्य कराए 11 हजार 782 रुपए तथा गोबर खरीदी में न्यत्र 12 हजार 654 रुपए, कुल 24 हजार 436 रुपए की राशि संबंधितों से वसूली योग्य बताया गया था। इसके सरपंच एवं सचिव द्वारा 30 जुलाई 2024 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई के खिलाफ धरना

रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामानुजगंज ने धरना प्रदर्शन किया। शहर के जय स्तंभ चौक पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल हुए। देशभर में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ नियमित रूप से ईंधन आपूर्ति कम का मुद्दा हावी रहा। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजय गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीजल पेट्रोल के कीमत में तीन रूपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। उसके बाद भी किसानों को डीजल समय पर नहीं मिल पा रहा है। अब खरीफ का समय है और किसान परेशान हैं। कांग्रेस नेताओं

ने कहा कि हमने आज यहां कई किराना दुकान में भी पहुंचकर दुकान संचालकों से बात की।उन्होंने बताया कि आज खाद्य तेल चाहे सोयाबीन तेल हो या सरसों तेल चाहे अन्य चीजों की बार करें तो आज महंगाई अपने चरम सीमा पर है। हमारे मिडिल क्लास के लोगों का सोर्स ऑफ इनकम नहीं बढ़ा है लेकिन उनका

खर्चा बढ़ गया है। देश में सोने की खरीदी सालभर बंद रखने का आह्वान पर भी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और बीजेप को घेरा। कहा उनकी अपील से सर्राफ व्यवसाय ठप हो गया है। सोने चांदी के व्यापारियों, कारीगरों एवं कर्मचारियों के रोजी-रोटी के संकट पर गया है। इसे लेकर ही कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है।

■ 19 गांवों के लोगों को सरकार की चलाई रही योजनाओं की जानकारी दी गई. ग्रामीणों की शिकायतें भी प्रशासन ने सुनी.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार का आयोजन चल रहा है। सुशासन तिहार के तहत सीएम और अफसर गांव में पहुंचकर चौपाल और शिविर लगा रहे हैं। शिविर के माध्यम से जहां सरकार के काम काज का फीड बैक लिया जा रहा है। वहीं अफसर शिविर के जरिए आम जनता की सीधे शिकायते सुन रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को कोरिया के बैकूंटपुर जनपद पंचायत के करहियाखांड में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 19 गांव के ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीणों ने जहां जिला प्रशासन की टीम को अपनी शिकायत सुनाई वहीं उनको अपनी जरूरतों के बारे में भी बताया। जिला प्रसासन ने भी लोगों को बताया कि शासन की ओर से कितनी योजनाएं उनके लिए चलाई जा रही है। इस मौके पर कई सैकड़ों ग्रामीणों ने अपनी समस्या के समाधान के लि आवेदन भी जिला प्रशासन को सौंपा।



बैकूंटपुर विधानसभा के विधायक भईयालाल राजवाड़े ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। महतारी वंदन योजना के माध्यम से विवाहित महिलाओं को हर माह 1 हजार की सहायता राशि सीधे खातों में दी जा रही है। साथ ही गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। राजवाड़े ने ग्रामीणों से पीएम सूर्यधर योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की अपील करते हुए कहा, शासन की योजनाएं आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के

उद्देश्य से संचालित की जा रही हैं, आप उनका लाभ लें।कलेक्टर रोकित्मा यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले भर में क्लस्टरवार जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन स्वयं गांवों तक पहुंचकर नागरिकों की समस्याएं सुन रहा है और उनके निराकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ सुदूर अंचलों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता में शामिल है। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदाय योजना, विवाह प्रोत्साहन योजना, मोटराइज्ड ट्रायसायकल पंजीयन और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की जानकारी दी गई। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना, नोनी सुरक्षा योजना, नवाबिहान योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, पोषण अभियान एवं महिला स्व-सहायता समूह सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी गई।

महासमुंद पुलिस ने 48 घंटे के भीतर शातिर चोर को पकड़ा

महासमुंद। सांकरा थाना पुलिस ने चोरी की शिकायत दर्ज होने के बाद महज 48 घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की रकम जो 2 लाख 30 हजार है, बरामद की है। गौरतलब है की जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर चोरी की घटना पर चोर को तो तत्काल पकड़ लिया जाता है, लेकिन 2 दिन पूर्व स्कू और कलेक्टर बंगले के पीछे की कॉलोनी में हुए चोरी का वादात का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। सांकरा थाना पुलिस के मुताबिक 18 मई 2026 को प्रार्थी देवेंद्र जोशी ने थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि 16 मई की रात अज्ञात चोर उसके घर की पेटी में रखे 2 लाख 30 हजार रुपये चोरी कर फरार हो गया। यह रकम अटल आवास, केसीसी लोन एवं धान बिजली से प्राप्त हुई थी, जिसे घर निर्माण के लिए रखा गया था।शिकायत मिलने के बाद थाना सांकरा में अपराध क्रमांक 99/26 धारा 305(ए), 331(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।

संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल रमेन डेका जनगणना

प्रक्रिया में हुए शामिल



बुधवार को लोकभवन में नगर निगम के अधिकारी पहुंचे, राज्यपाल रमेन डेका ने जनगणना कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान अधिकारियों ने जनगणना के सामान्य 33 बिंदुओं से संबंधित जानकारी राज्यपाल से प्राप्त की। जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत अधिकारियों ने निर्धारित प्रश्नों के आधार पर राज्यपाल से विभिन्न जानकारीयां लीं, जिनमें व्यक्तिगत, सामाजिक एवं अन्य सामान्य विवरण शामिल रहे। राज्यपाल डेका ने जनगणना कार्य में सहयोग करते हुए सभी आवश्यक जानकारीयां उपलब्ध कराईं। इस अवसर पर नगर निगम रायपुर की जोन कमिश्नर – 4 सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर के बाद दुर्ग-बिलासपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी

रायपुर। राजधानी रायपुर के बाद दुर्ग और बिलासपुर में भी कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने पर विचार किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आग्रह करने की बात कही है। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। छोटे-छोटे विषय विभिन्न विभागों के कारण पेंडिंग हुआ करते थे। अभी रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू है। आवश्यकता अनुरूप इसका विस्तार होना चाहिए। मुख्यमंत्री साय से इसे बिलासपुर और दुर्ग में भी प्रारंभ करने के लिए आग्रह करेंगे।

11 परियोजना अधिकारी और 30 पर्यवेक्षक हुए इधर से उधर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग में फेरबदल हुआ है। बड़ी संख्या में परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों का तबादला किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद यह तबादला आदेश जारी किया गया है। सरगुजा, कोरिया, जशपुर, बिलासपुर, बेमेतरा समेत कई जिलों के अधिकारियों को प्रभावित किया गया है। कुछ अधिकारियों को ग्रामीण परियोजनाओं से शहरी परियोजनाओं में भेजा गया है, जबकि कई अधिकारियों को अन्य जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुल 11 परियोजना अधिकारी और 30 पर्यवेक्षकों को इधर से उधर किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशाली हो गया है। स्थानांतरण सूची में रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, सकी, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, बेमेतरा, रायगढ़, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर और बीजापुर जिलों के अधिकारी शामिल हैं।

राज्यपाल से प्रख्यात लोक कलाकार तीजन बाई के परिजनों ने की सौजन्य भेंट



लोकभवन में प्रख्यात लोक कलाकार एवं पंडवानी गायिका श्रीमती तीजन बाई के परिजनों ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने तीजन बाई के स्वास्थ्य की जानकारी साझा की। राज्यपाल डेका ने पंडवानी की विश्वविख्यात कलाकार तीजन बाई के स्वास्थ्य का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ तथा उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। चर्चा के दौरान तीजन बाई के परिजनों ने बताया कि उनके सम्मान में आगामी 7 अगस्त को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। परिजनों ने इस अवसर पर राज्यपाल डेका को समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। इस अवसर पर तीजन बाई की पुत्रवधू श्रीमती वेणु देशमुख सहित परिवार के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

राज्यपाल डेका ने पर्यटन स्थलों का विकास एवं सुविधाएं बढ़ाने के लिए निर्देश

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका से बुधवार को लोकभवन में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक आचार्य ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान राज्य में पर्यटन स्थलों के विकास, विस्तार और पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राज्यपाल ने पर्यटन क्षेत्र को अधिक आकर्षक और सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव और आवश्यक निर्देश दिए। राज्यपाल डेका ने बेस्तर के चित्रकूट जलप्रपात, धमतरी जिले के गंगरेल तथा कोरबा जिले के बुका जलाशय में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग यहां आने के लिए आकर्षित हों। राज्यपाल ने पर्यटन स्थलों को वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी अधिक सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों के विकास में बुजुर्ग पर्यटकों के लिए आवागमन और अन्य आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जाए।

राजधानी/छत्तीसगढ़

शहर को सुत्यवस्थित और जनसुविधाओं से समृद्ध बनाने लगातार किए जा रहे कार्य : चौधरी

वित्त मंत्री ने रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास

रायपुर। वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए कहा कि रायगढ़ शहर को सुव्यवस्थित, आधुनिक और जनसुविधाओं से समृद्ध बनाने के उद्देश्य से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर के विकास में अधोसंरचना विस्तार, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सुविधाओं और युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने नगर निगम के वार्ड क्रमांक 28 में विधायक निधि से लगभग 20 लाख रुपये की लागत से निर्मित साहू समाज सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवन सामाजिक गतिविधियों, बैठकों, सांस्कृतिक आयोजनों और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ऐसे भवन समाज के लोगों को सुविधाजनक स्थान



उपलब्ध कराते हैं और सामाजिक समन्वय को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले साहू समाज के छात्र-छात्राओं को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

वार्ड क्रमांक 21, श्रीराम कॉलोनी में अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर

के अंतर्गत लैंडस्केपिंग, पौधरोपण, मुख्य द्वार, बाउंड्रीवाल, विद्युतीकरण, बच्चों के खेल उपकरण, बैठने की व्यवस्था सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि इस उद्यान के विकसित होने से बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक स्थल मिलेगा तथा शहर के हरित क्षेत्र में वृद्धि

देशभर में मेडिकल दुकानें बंद, ऑनलाइन

फॉर्मसी के विरोध में हड़ताल

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री बोले- मरीजों को नहीं होने देंगे परेशानी

रायपुर। ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रुगिस्ट्स के नेतृत्व में देशभर में बुधवार को मेडिकल स्टोर बंद था। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दवा विक्रेता ऑनलाइन फॉर्मसी और नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दवा विक्रेताओं की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि लोकतंत्र में हर वर्ग को अपनी बात रखने और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का पूरा अधिकार है लेकिन मरीजों को परेशानी नहीं होने देंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवा विक्रेताओं की समस्या और मांगों को गंभीरता से लिया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवा विक्रेताओं की ओर से ऑनलाइन दवा विक्री सहित अन्य मुद्दों को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान भी दवा व्यवसायियों ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री और उससे जुड़े प्रभावों को लेकर भारत सरकार के समक्ष अपनी आपत्तियां और सुझाव रखे थे।

श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा



वर्तमान में भी जो स्थिति बनी हुई है, वह मुख्य रूप से केंद्र सरकार से जुड़ा विषय है, इसलिए इस पर अंतिम निर्णय भारत सरकार स्तर पर ही लिया जाएगा, लेकिन मरीजों को असुविधा ना हो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरी तरह सतर्क और अलर्ट मोड पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दवा दुकानों के बंद रहने की स्थिति में भी मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी बनाए हुए है। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता, उपचार व्यवस्था और जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि आम लोगों को समय पर इलाज और आवश्यक दवाएं मिलती

रहें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और अस्पताल प्रबंधन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं तथा जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं। महासमुंद जिले में भी

ऑनलाइन फार्मसी के खिलाफ दवा कारोबार एकजुट दिखे। जिले की थोक एवं चिल्लर दवा विक्रेताओं ने लामबंद होकर अपनी दवा दुकानों को एक दिवसीय बंद रखा। इस आंदोलन को समर्थन देते हुए जिला दवा विक्रेता संघ महासमुंद ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

जिला दवा विक्रेता संघ के सचिव अरशी अनवर ने बताया कि ऑनलाइन फार्मसी कंपनियां भारी छूट देकर पारंपरिक दवा व्यापार को प्रभावित कर रही हैं। संघ ने आरोप लगाया कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्मस पर बिना उचित सत्यापन के नकली, प्रतिबंधित और संवेदनशील दवाओं की बिक्री धड़ल्ले से सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि आम लोगों के समय पर स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है।

मारपीट और जातिगत टिप्पणी करने वाला गोल्डी शर्मा गिरफ्तार

रायपुर। आरंग विकासखंड स्थित गुदगुदा ग्राम पंचायत में सतनामी समाज के व्यक्ति से मारपीट और जातिगत टिप्पणी करने के मामले में आरंग पुलिस आखिरकार मुख्य आरोपी गोल्डी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।

बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले गांव में भैंसों से भरे वाहन को रोकने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसी विवाद के बाद कथित गौ सेवक गोल्डी शर्मा और उसके साथियों पर सतनामी समाज के सदस्य बलराम कुर्छे के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगा था। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें आरोपी



किसान के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करते नजर आया। सबसे गंभीर आरोप यह है कि मारपीट पुलिस थाने के सामने ही की गई।

वीडियो वायरल होने के बाद सतनामी समाज में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में समाज के लोग आरंग थाने पहुंच गए और थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात को देखते हुए

आरंग थाना परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया और भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इस मामले में विरोध बढ़ने के बाद पुलिस ने गोल्डी शर्मा और उसके अन्य साथियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था।

अब मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

रायपुर में दौड़ेगी डायल-112 की 54 नई गाड़ियां डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने दिखाई हरी झंडी

■ **दीपक बैज का मोबाइल नहीं मिलने पर कही ये बात**

रायपुर। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने रायपुर को 54 नई डायल 112 गाड़ियों की सौगात दी है। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर सभी गाड़ियों को रवाना किया। इस दौरान शर्मा ने कहा, डायल 112 करने पर अब और तेजी से पुलिस पहुंचेगी। C-DAC की एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए पूरा सिस्टम मॉनिटर होगा। कॉल आते ही पुरंत लोकेशन ट्रेस होगी।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, नई गाड़ियों में हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। कमांड सेंटर से लाइव मॉनिटरिंग होगी। आज से ही नई गाड़ियां सेवा में शामिल होंगी। इसके लिए उन्होंने गृहमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया। ड्रोन पेट्रोलिंग को लेकर डिप्टी



सीएम विजय शर्मा ने कहा, अब ड्रोन पेट्रोलिंग सिस्टम पर भी काम किया जाएगा। कस्टमाइज लोकेशन पर ड्रोन भेजे जाएंगे। टेक्नोलॉजी के जरिए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी।

पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल 8 माह बाद भी नहीं मिला। बैज के इस बयान पर डीसीएम विजय शर्मा ने कहा, उन्होंने कहीं कोई कप्लेन किया होगा तो मामले को दिखवाते हैं।

112 गाड़ियों के जवानों पर हमले के सवाल पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, जवानों पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कानून के तहत कड़ी सजा का प्रावधान है। गड़बड़ी करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

केंद्रीय गृहमंत्री के बयान भेष बदलकर कुछ लोग आर्येंगे सावधान रहें, अपनी चुनी सरकार पर भरोसा रहें, मामले पर डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा, बेस्तर के सीधे-साधे सजाों को पहले भी बरगलाया गया। वहां के लोगों को जनप्रतिनिधियों और लोकतंत्र पर भरोसा रखना होगा। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप लोकतंत्र पर विश्वास करें।

निधि से

लगभग 46 लाख रुपये की लागत से बाल उद्य 1 न जोर्णोंद्वार कार्य का शिलान्यास किया गया। इस स परि योजना होगी। रायगढ़ स्टेडियम के पीछे से श्रीराम कॉलोनी मोड़ तक लगभग 37.88 लाख रुपये की लागत से 580 मीटर लंबी नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। इस निर्माण से क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था में सुधार होगा और बरसात के दौरान होने वाली समस्याओं में कमी आएगी। चौधरी ने कहा कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल निकासी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि रायगढ़ में सड़क, पुल, केलो नदी तट विकास, तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान निर्माण और ऑक्सीजन जोन जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है। इतवारी बाजार क्षेत्र को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को स्वच्छ और हरित वातावरण

सियान गुड़ी बन रही वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहारा और सम्मान का केंद्र

32 को मिल रही नियमित फिजियोथेरेपी सुविधा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित सियान गुड़ी बुजुर्गों के लिए देखभाल, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक जुड़ाव का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रही है।

समाज कल्याण विभाग की इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत जिले में अब तक 94 वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से 32 बुजुर्गों को नियमित रूप से फिजियोथेरेपी की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें शारीरिक समस्याओं से राहत मिल रही है।

हाल ही में जिला अस्पताल की विशेषज्ञ टीम, जिसमें चिकित्सा अधिकारी, मनोवैज्ञानिक, साइकेट्रिक नर्स और लैब तकनीशियन शामिल थे, इस टीम ने सियान गुड़ी और नशाफिक केंद्र के हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं रक्त जांच किया। टीम ने वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श,



मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सलाह और कार्डसिलिंग भी प्रदान की।

सियान गुड़ी में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से वरिष्ठ नागरिक विभिन्न मनोरंजक, सामाजिक और स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियों में भाग लेते हैं। दिनभर की गतिविधियों के बाद शाम 6 बजे सभी पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों की उपस्थिति में सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, जिससे आध्यात्मिक और मानसिक शांति

का वातावरण बनता है। सियान गुड़ी से लाभान्वित वरिष्ठ नागरिकों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह केंद्र उनके लिए सम्मान, देखभाल और आत्मीयता का स्थान बन गया है। समाज कल्याण विभाग ने जिले के सभी वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में सियान गुड़ी पहुंचकर इस उपयोगी सुविधा का लाभ उठाएं।



आयोजित की जा रही है जिसमें विद्यार्थी, महिलाएं तथा अन्य सामान्यजन भी पंजीयन कर भागीदारी कर सकते हैं । आम महोत्सव में पंजीयन एवं प्रवेश पूर्णतया निशुल्क है। इस आयोजन में संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगी भी सहभागी हो सकते हैं।

आम महोत्सव के प्रथम दिवस 29 मई को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक प्रविष्टियों का पंजीयन किया जाएगा। सामान्यजनों के अवलोकनार्थ यह प्रदर्शनी तीनों दिन रात्रिऋ 9 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में आम की विभिन्न किस्मों के फल, आम के

विभिन्न उत्पाद एवं आम के पौधे भी विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगे। द्वितीय दिवस 30 मई को आम उगाने वाले कृषकों एवं जिज्ञासुओं के लिए 12 बजे से 4 बजे तक तकनीकी मार्गदर्शन एवं परिचर्चा का आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में उच्च गुणवत्ता के आम की विभिन्न किस्मों का उत्पादन, आम के विभिन्न उत्पादों के प्रसंस्करण एवं उनके विण्णन के साथ ही आम उत्पादन हेतु छत्तीसगढ़ शासन की योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की जायेगी, जिससे नयी पीढ़ी के लोग आम उत्पादन की ओर आकृष्ट हो सकें आम उत्पादन को पर्यावरण के संरक्षण के साथ एक स्वास्थ्यवर्धक व्यवसाय के रूप में अपनाने की जानकारी आम लोगों को प्रदान की जा जाएगी। तृतीय दिवस 31 मई को आम उत्पादक कृषकों एवं उद्यमियों की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी 12 से 4 बजे तक सुनाई जाएगी।

कार्यालय अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर निविदा आमंत्रण तिथि :-18.05.2026 ई-प्रोक्वोरमेंट निविदा सूचना 01. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये Log in करें http://eproc.cgstate.gov.in 02. संबंधित संधाग-स.क्र. 1 से 7 अम्बिकापुर एवं स.क्र. 8 सूरजपुर संधाग 03. स.क्र. 01 'स' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार एवं स.क्र. 02 से 08- 'द' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार 04. ऑनलाईन निविदा डालने की अंतिम तिथि 10.06.2026			
सरल क्र	एच.आई.टी. क्र	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3	4
1	25	लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंधाग क्रं. 1 अम्बिकापुर के अंतर्गत विभिन्न शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का रंगाई पोताई का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	131.66
2	26	लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंधाग क्रं. 1 अम्बिकापुर के अंतर्गत विकासखण्ड लखनपुर एवं उदयपुर में विभिन्न शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का रंगाई पोताई का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	27.60
3	27	लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंधाग क्रं. 1 अम्बिकापुर के अंतर्गत विभिन्न शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	15.00
4	28	लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंधाग सीतापुर के अंतर्गत विभिन्न शासकीय आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का साधारण मरम्मत का कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	15.00
5	29	लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंधाग क्रं. 2 अम्बिकापुर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में डब्ल्यू एम एस पैच रिपैर का कार्य इमल्शन के साथ। (प्रथम आमंत्रण)	14.99
6	30	लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंधाग सीतापुर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में डब्ल्यू एम एस पैच रिपैर का कार्य इमल्शन के साथ। (प्रथम आमंत्रण)	15.00
7	31	लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंधाग क्रं. 1 अम्बिकापुर के अंतर्गत विभिन्न मार्गों में डब्ल्यू एम एस पैच रिपैर का कार्य इमल्शन के साथ। (प्रथम आमंत्रण)	15.00
8	32	शासकीय पोलिटैक्निक परिसर सूरजपुर में 06 नग जी टाईप क्वार्टर का निर्माण कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	73.13
अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर			
जी – 262700815/10			

पेपर लीक का बम प्रधान पर फोड़ने की तैयारी में राहुल

सनत जैन

लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाथ में नीट–यूजी पेपर लीक का बम आ गया है। यह ऐसा बम है, जिसमें लाखों युवा और उनके करोड़ों परिवारजन का भविष्य और नाराजी जुड़ी हैं। करोड़ों लोगों को प्रभावित करने वाले इस बम को लेकर, राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने लगातार परीक्षा पेपर लीक होने के मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने या बर्खास्त करने की सीधी मांग कर दी है। देश के विभिन्न राज्यों में पेपर लीक की 80 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। नीट परीक्षा के 2024 में पेपर लीक हुए थे। इस परीक्षा में बड़ी संख्या में लोग 700 से ज्यादा अंक लेकर हजारों परीक्षार्थी पास हुए थे। जिनके एडमिशन एम्स और अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज में नीट परीक्षा परिणाम के बाद हुए थे। उस परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगे थे। उस समय यह मामला रफा–दफा हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के बीच में आ जाने के कारण ना तो दोबारा परीक्षा हुई, ना ही परीक्षा परिणाम को लेकर सरकार ने कोई जांच कराई। नीट परीक्षा में लगातार गड़बड़ी की शिकायत आती रही है। इस बार भी करीब 22 लाख छात्र–छात्राओं ने नीट के फॉर्म भरे थे। हजारों करोड़ों रुपए की फीस परीक्षार्थियों से वसूली गई। कोचिंग सेंटर में हजारों करोड़ों रुपए छात्र–छात्राओं ने खर्च किए हैं। कई छात्र–छात्राओं ने दो से तीन साल तक रात दिन मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी की थी। पेपर लीक हो जाने से सबके भविष्य में प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस मामले को लेकर लगभग सभी राज्यों के युवा अब सड़कों पर आ गए हैं। दक्षिण के राज्यों ने अलग तरह से प्रवेश परीक्षा संचालित करने की बात करना शुरू कर दी है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ही एक ऐसे नेता हैं, जिन्होंने खुलकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने या बर्खास्त करने का दबाव प्रधानमंत्री पर बनाना शुरू कर दिया है। इस्तीफे के इस बम को आसानी से डिफ्यूज कर पाना कष्ट सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बस की बात नहीं होगी। इस बार इस लड़ाई में राहुल गांधी के साथ बड़े पैमाने पर युवा भी साथ में है। रही सही कसर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बेरोजगारों और फर्जी डिग्री धारकों के लिए परजीवी होने तथा जो असंवेदनशील टिप्पड़ी की है, उसके बाद से युवाओं में नाराजी बढ़ गई है। न्यायपालिका पर विश्वास भी एक तरह से कम हो गया है। जांच एजेंसी सीबीआई हमेशा छात्रों पर कार्यवाही करती है। व्यापम से लेकर अभी तक दर्जनों बार व्यापम और नीट के जो पेपर लीक हुए हैं, उसमें कार्यवाही हमेशा निर्दोष छात्रों के ऊपर हुई है। कभी किसी भी धंधेबाज और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं की गई है। नैतिकता या जिम्मेदारी के आधार पर कुर्सी पर बैठे हुए नेताओं ने कभी इस्तीफा नहीं दिया है। जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जिसके कारण युवा नाराज होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। इस समय मंहगाई, बेरोजगारी तथा पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी के हाथ में एक ऐसा मौका लग गया है, जिससे वह सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। 12 साल में पहली बार मोदी सरकार के किसी मंत्री से, विपक्ष ने इस्तीफा के लिए दबाव बनाया है। यह दबाव खाली जाएगा, ऐसा दिखता नहीं है। राहुल गांधी अब विपक्ष की राजनीति करना सीख गए हैं। मौके का फायदा किस तरह से उठाया जाता है, यह जान गए हैं। वर्तमान स्थिति में छात्रों और युवाओं के गुस्से को देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान को ढाल बनाकर इस्तीफा देने का दबाव बना चुके हैं।

पुराण दिग्दर्शन

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)
युवनाश्व की कोख से मांधाता
पुराणों में लिखा है कि प्रसिद्ध सम्राट् मान्धाता का जन्म महाराजा युवनाश्व के पेट से हुआ था– यह कथा अत्यन्त असम्भव है। पुरुष पेट में न गर्भाशय होता है और नांही उसमें किसी बालक को धारण कर सकने की गुज्ञाइश होती है। अतः पुराणों का यह लेख कोरा गप्प गोला ही समझना चाहिए। हम सर्वप्रथम इस आख्यान का पौराणिक–स्वरूप प्रकट करते हैं–
पौराणिक स्वरूप
भार्याशास्त्रेन निविण्ण ऋद्योऽस्य कृपालवः। इष्टि स्म वर्तयां चक्रूरैर्द्वी ते सुसमाहिताः।।26।। राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तपितः। दृष्ट्वा शयानान्निप्रास्तान्यपौ मनञ्जलं स्वप्नम्।।27।। ततः काले उपावृत्ते कुक्षि निभिद्य दक्षिणम्। युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजान ह।।30।।

कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोच्यते भृशम्।। मान्धाता वत्स मारोदीरितीन्द्रो देशिनीमदात्।।31।। (श्रीभ्रमद्गवत 8।6।८–) अर्थात्] महाराजा युवनाश्व निःस्तान्न होने के कारण] सो स्त्रियों से दुःखित हो गया, तब कृपालु ऋषियों ने बड़ी ही तत्परता के साथ (स्तनान् प्राप्ति के लिये) इन्द्र का यज्ञ रचा।।26।।रात के समय व्यास से अत्यन्त पीड़ित हुआ राजा यज्ञशाला में पहुँचा सब ऋत्विजों को सोते देखकर स्वयं ही मन्त्रों से अभिमन्त्रित किया हुआ यज्ञ–कलश का जल पी गया।।27।। (क्योंकि यह जल पुंसवन्–मन्त्रों से अभिमन्त्रित होने के कारण पुत्रोत्पादन की अचूक सामाथ्य से परिपूरित था अतः) कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद युवनाश्व की दाईं कोख को फाड़ कर एक चक्रवर्ती–लक्ष्णोपेत वालक का प्रादुर्भाव हुआ।।।30।।

क्रमशः ...



फिर कैसे मिले सुर मेरा-तुम्हारा

अमेश चतुर्वेदी

विधानसभा चुनावों में बड़े विपक्षी चेहरों की बड़ी नाकामी से विपक्षी खेमे में खलबली मच गई है। बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता बनर्जी की हार ने विपक्षी खेमे के उन दलों के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई हैं, जो इन चुनावों से बेपरवाह थे। केरल की गठबंधन सरकार में वापसी की वजह से कांग्रेस थोड़ी राहत में भले ही हो, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय दलों को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगा है। तमिलनाडु में सत्ता की चाहत में विपक्षी गठबंधन टूट भी चुका है। कांग्रेस के हाथ ने डीएमके का बरसों पुराना साथ छोड़ नवेली टीवीके का दामन थाम लिया है। दूसरी तरफ थांधली का आरोप लगाने के साथ ही ममता बनर्जी को विपक्षी एकता, खासकर इंडिया ब्लाॅक की याद आने लगी है। अब उन्हें विपक्षी एकता मजबूत करने की याद भी आने लगी हैं।

दिलचस्प यह है कि अतीत में इंडिया ब्लाॅक की एकता से बेपरवाह रहें ममता को अब उसी की बहुत याद आने लगी है। वैसे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी कम गलतियां नहीं हुई हैं। राहुल गांधी का पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त के लिए ममता को खुलेआम जिम्मेदार ठहराना एक तरह से तुलामूल की तावूत का कोल ही साबित हुआ। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि विपक्षी एकता का विचार सिर से परवान चढ़ सकता है ? अतीत में एकता को लेकर जिस तरह विपक्षी खेमे में एक–दूसरे को शह और मात देने का खेल चला है, उससे क्या मुकदमल एकता की उम्मीद बचती है ? 2024 के आम चुनावों के पहले विपक्षी राजनीति को एक मंच पर लाने और भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन आपसी टकराव और वर्चस्व के चलते यह हकीकत नहीं बन पाया। 23 जून 2023 को पटना में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुआई में विपक्षी क्षत्रपों की बैठक में इंडिया ब्लाॅक बनाने का फैसला तो हुआ,लेकिन नेतृत्व के मुद्दे पर एक राय नहीं बन पाई। नीतीश



कुमार ने खुलकर भले ही कभी नहीं कहा, लेकिन उनकी चाहत थी कि विपक्षी गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया जाय। लेकिन कांग्रेसी आलाकमन की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल कांग्रेस विपक्षी राजनीति की लगाम खुद के हाथ में ही रखना चाहती है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन का साथ तो उसे चाहिए, लेकिन इनमें से किसी का भी नेतृत्व उसे गवारा नहीं। अपने पहले परिवार की पूरी स्वीकार्यता भले ही ना हो, लेकिन अगुआई कांग्रेस को ही चाहिए। यही वजह है कि विपक्षी राजनीति के सबसे ज्यादा स्वीकार्य चेहरा रहे नीतीश कुमार ने निराशा में उसी मोदी का हाथ थाम लिया, जिनसे वे दूर हो चुके थे। इसके बाद का इतिहास सबको पता है।

ममता को राजनीति में पहला बड़ा ब्रेक बेशक राजीव गांधी ने दिया, लेकिन वाममोर्चा के साथ राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेसी सहयोग ने उन्हें बाद के दिनों में गांधी–नेहरू परिवार से दूर कर दिया। हालिया हार के बावजूद अपनी संघर्षशीलता के चलते ममता विपक्षी राजनीति का अब भी बड़ा चेहरा हैं। उनकी अपनी छवि अक्सर राहुल गांधी पर भी भारी पड़ती है। इंडिया ब्लाॅक के विचार के वक्त पूर्व कांग्रेसी होने के नाते ममता को पता था कि कांग्रेस अपने हाथ में नेतृत्व बनाए रखने के लिए हर मुश्किल कोशिश करेगी, इसीलिए उन्होंने ही नीतीश कुमार और लालू यादव को पहली बैठक पटना में कराने का सुझाव दिया था। बाद के दिनों में कांग्रेस ने जैसी चाल चली, उससे विपक्षी एकता का राग बेसुरा हो गया। जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव नतीजों में

ज्ञान/मीमांसा

नवा रायपुर अटल नगर: विकास, निवेश और आधुनिक भारत का उभरता स्मार्ट शहर

सुनील कुमार त्रिपाठी, सहायक संचालक

और योजनाबद्ध राजधानी नवा रायपुर अटल नगर आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे स्मार्ट शहरों में शामिल है। सुव्यवस्थित अधोसंरचना, हरित विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, पर्यटन और महिला सशक्तिकरण जैसे विविध क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति ने नवा रायपुर को भविष्य के भारत का आदर्श शहरी मॉडल बना दिया है। यह केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि निवेश, नवाचार और समावेशी विकास का उभरता हुआ केंद्र है।

स्मार्ट अधोसंरचना और शहरी सेवाओं में बड़ी उपलब्धियाँ

नवा रायपुर अटल नगर में 52 एमएलडी क्षमता की पाइपलाइन और अत्याधुनिक जल शोधन संयंत्र के माध्यम से पूरे शहर में दीर्घकालिक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इससे वर्तमान आबादी के साथ-साथ नए विकसित हो रहे सेक्टरों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सकेगी।

वर्षाजल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए 10.66 किलोमीटर लंबी बायोस्वेल्स, रिचार्ज पिट्स और प्राकृतिक जल निकासी तंत्र विकसित किए गए हैं। इन पहलों ने न केवल जल संरक्षण को मजबूत किया है, बल्कि शहर के पर्यावरणीय संतुलन को भी सुदृढ़ किया है।

परिवहन और कनेक्टिविटी को मिला नया आयाम

रायपुर–राजिम रेल सेवा का नवा रायपुर के सीबीडी स्टेशन तक विस्तार शहर की कनेक्टिविटी को नई गति प्रदान कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षित आवाजाही और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पिंग ई–रिक्शा सेवा शुरू की गई है। साथ ही, ई–बस संचालन के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और सेवा प्रारंभ होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह पहल हरित और टिकाऊ शहरी परिवहन को दिशा में महत्वपूर्ण



कदम है।

शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हो रहा एडुसिटी

नवा रायपुर के 13 सहकारी विद्यालयों का उन्नयन किया गया है और दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में एडुसिटी का विकास किया जा रहा है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों जैसे National Institute of Fashion Technology (NIFT), National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) ४6०० National Forensic Sciences University (NFSU), Narsee Monjee को भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सेक्टर–7 में 17 एकड़ भूमि पर आवासीय विद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है।

मेडिसिटी- स्वास्थ्य सेवाओं का नया केंद्र

मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में विश्वस्तरीय मेडिसिटी विकसित की जा रही है। यहाँ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डायग्नोस्टिक सेंटर, धर्मशाला, होटल और आवासीय सुविधाएँ विकसित की जाएँगी।

इस परियोजना के तहत ऋग्मद्बुद्ध4।॥शब्दश्रद्धद्बुद्ध को 300 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। साथ ही, लगभग 50 एकड़ भूमि पर आवासीय विकास हेतु निजी निवेशकों को

भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें लगभग 350 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है।

महिला सशक्तिकरण और श्रमिक कल्याण

कार्यरत महिलाओं के लिए 1,000 क्षमता वाले वर्किंग युमन हॉस्टल का निर्माण 109 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। यह परियोजना महिला सुरक्षा, सुविधा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी।

इसके अतिरिक्त, प्रवासी श्रमिकों के लिए 1,100 क्षमता वाला सर्वसुविधायुक्त श्रमिक आवास भवन 40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है।

सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी

का उभरता हब

नवा रायपुर में राज्य का पहला स्क्व आधारित एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपये का निजी निवेश अपेक्षित है।यहाँ भारत का पहला बड़ुह तकनीक आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए भी भूमि आवंटित की गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर (छन्ः) हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है, जहाँ ऋक्क प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग और श्रृक्ष टेस्टिंग जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।

सीबीडी क्षेत्र में प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर आईटी कंपनियों को सुसज्जित कार्यालय स्थान

राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस

दिलीप कुमार पाठक

हर साल 21 मई को पूरा देश राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाता है। अखबारों की रस्मी खबरों और सरकारी बयानों के बीच क्या हम कभी सोचते हैं कि इस दिन की असली ज़रूरत क्या है?

21 मई हमारे इतिहास का वह काला दिन है जिसने देश की सुरक्षा और राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी दिन तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे की आत्मघाती हमलावर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। वह धमाका सिर्फ एक नेता की मौत नहीं, बल्कि भारत की संप्रभुता पर सीधा हमला था, जिसने देश को हिलाकर रख दिया।

इस दर्दनाक हादसे के बाद तत्कालीन केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया।



राजीव गांधी के बलिदान को

याद रखने और देश को इस

खतरे के खिलाफ एकजुट

करने के लिए हर साल 21 मई

को आधिकारिक तौर पर यह

दिवस मनाने की शुरुआत हुई।

इस दिवस की स्थापना के पीछे का

रणनीतिक संदेश बिल्कुल साफ था – देश

को सचेत करना कि नफरत और कट्टरता

की राजनीति राष्ट्र के सामाजिक ताने–बाने

को कितना गहरा और लाइलाज जख्म दे

सकती है। लेकिन तीन दशकों से अधिक

का समय बीत जाने के बाद भी हालात

कितने बदले हैं? सोचने वाली बात है।

आज भी जब हम सुबह की चाय के साथ

अखबार खोलते हैं, तो सुर्खियां किसी

आतंकी साजिश, धमाके या मासूमों के

खून से सनी होती हैं। यह स्थिति इस

केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया।

करती है कि नीतिगत और सामाजिक स्तर पर हमसे चूक कहां हो रही है? दरअसल, हमारी सबसे बड़ी भूल यह रही कि हमने आतंकवाद को महज सरहद की समस्या और

सैन्य सुरक्षा का मामला मान लिया। हमने

मान लिया कि सीमाओं पर मुस्तैद फौज

और सुरक्षा बलों की बंदूकें हमारा सुरक्षा

कवच हैं, और बतौर नागरिक हमारी

जिम्मेदारी खत्म हो गई। यही वह वैचारिक

ढीलापन है जहां हम गचना खा रहे हैं,

क्योंकि आतंकवाद ने अपना पारंपरिक

चोला बदल लिया है। अब इसके ठिकाने

किसी सुदूर घाटी, बंद कमरों या घने

जंगलों तक सीमित नहीं हैं; इसका नया

युद्धक्षेत्र हमारे ड्राइंग रूम और युवाओं की

कट्टरपंथ का दौर है, जहां किसी मासूम के

ब्रेनवांश के लिए न तो भौतिक रूप से आमने–सामने आने की ज़रूरत है और ना ही किसी ट्रेनिंग कैंप की। सोशल मीडिया और डाक़ वेब पर तैरता एक छोटा सा भड़काऊ वीडियो, कोई फेक न्यूज या एडिटेड विजुअल किसी भी संवेदनशील युवा के मन में नफरत का बारूद भरने के लिए काफी है।

आतंकवाद न तो किसी मजहब की बपौती है और न ही इसकी कोई राष्ट्रीयता होती है, इसका एकमात्र एजेंडा समाज में अविश्वास की खाई खोदना और देश के सांप्रदायिक सौहार्द को पंगु बनाना है। जब कोई आत्मघाती हमला या विस्फोट होता है, तो बारूद के वो छर्रें किसी का मजहब या जाति देखकर रास्ता नहीं बदलते। वे सिर्फ इंसानी बस्तियों को उजाड़ते हैं और हंस्ते–खेलते परिवारों के भविष्य को हमेशा के लिए दफन कर देते हैं।

आज का इतिहास

- 1881 यूएस नेशन लॉन टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई।
- 1894 मैनचेस्टर शिप नहर, नॉर्थवेस्ट इंग्लैंड में ग्रेटर मैनचेस्टर को आयरिश सागर से जोड़ता है, आधिकारिक तौर पर खोला गया, उस समय दुनिया में सबसे बड़ी नहर नहर बन गई।
- 1904 पेरिस में फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ (फीफा) की स्थापना हुई।
- 1911 मैक्सिकन राष्ट्रपति पोर्फिरियो डिआज़ और क्रांतिकारीफ्रांसिस्को मादेरो ने दोनों पुरुषों की सेनाओं के बीच लड़ाई को समाप्त करने के लिए स्प्टाद जुआरेज़ की संधि पर हस्ताक्षर किए, और इस तरह मैक्सिकन क्रांति के समापन चरण का समापन हुआ।
- 1917 संयुक्त राज्य अमेरिका में 1917 में ग्रेट अटलांटा की आग में 300 एकड़ नष्ट हो गए।
- 1918 अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने महिलाओं को मतदान को अनुमति दी।
- 1924 शिकागो विश्वविद्यालय के छात्र रिचर्ड लोएब और नाथन लियोपोल्ड, जूनियर। एक रोमांचक अपराध में एक 14 साल के लड़के की हत्या करना एक सटीक अपराध की इच्छा करता है।
- 1927 यूनाइटेड किंगडम ने राजा अब्दुल अजीज़ की संप्रभुता को 20 मई, 1927 को जेद्दा की संधि पर हस्ताक्षर करके हेजाज़ और नेज्द के राज्यों में मान्यता दी। हन्जाज और नेज्द को 1932 में सऊदी अरब के राज्य में मिला दिया गया था।
- 1927 सेंट लुइस की आत्मा को आत्मसात करते हुए, अमेरिकी एंक्विपटर चार्ल्स लिंडबर्ग ने न्यूयॉर्क सिटी से पेरिस – ले बोरगेट एयरपोर्ट के पास पहली एकल नॉन-स्टॉप ट्रांसाटलांटिक उड़ान, फ्लाईफ़ार्म रूजवेल्ट फ़ील्ड को पूरा किया।
- 1937 उत्तरी ध्रुव –1, सोवियत और रूसी मानवयुक्त स्टेशन, 21 मई, 1937 को आर्कटिक महासागर के बहाव वाले बर्फ पर संचालित होने वाले पहले वैज्ञानिक अनुसंधान निपटान बन गया।
- 1946 मैनहट्टन प्रोजेक्ट के भौतिक विज्ञानी लुइस स्लोटिन ने लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में गलती से विखंडन प्रतिक्रिया शुरू कर दी और खुद को कठिन विकिरण की घातक खुराक दी, जिससे वह इतिहास में एक महत्वपूर्ण दुर्घटना का शिकार हो गया।
- 1998 इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुहार्तो ने अपने तीन दशक लंबे शासनकाल के समर्थन के परिणामस्वरूप इस्तीफा दे दिया।

बांग्लादेशी घुसपैठियों के चेहरे पर दिख रहा खौफ

नीरज कुमार दुबे

बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ के रास्ते बंद होने की आशंका ने सीमापार बैठे घुसपैठियों और तस्करी गिरोहों के मन में खौफ पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है कि कड़ी निगरानी और तेजी से होने वाली बाइबंदी की संभावना को देखते हुए कुछ अवैध घुसपैठिये खुद ही वापस लौटने लगे हैं, जबकि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों ने भी भारत में घुसपैठ की अपनी योजना बदल दी है जो अब तक पश्चिम बंगाल की ढीली सीमा व्यवस्था का फायदा उठाने की सोच रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह राज्य में डबल इंजन सरकार का गठन माना जा रहा है, जिसने सत्ता संभालते ही राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बड़ा कदम उठाया है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चिकन्स नेक गलियारों में सीमा सुरक्षा बल को लगभग एक सौ बीस एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि भारत बांग्लादेश सीमा पर बाइबंदी और सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बनाया जा सके। इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मंजूरी भी दे दी गई है, ताकि सीमा सुरक्षा, सैन्य आवाजाही और संपर्क ढांचे को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

हम आपको बता दें कि चिकन्स नेक गलियारा पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में स्थित वह संकरा भूभाग है जिसकी चौड़ाई लगभग बाईस किलोमीटर है। यही गलियारा देश के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर के आठ राज्यों से जोड़ता है। यह क्षेत्र नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा होने के कारण रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। लंबे समय से इस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा, सड़क संपर्क और आपदा प्रबंधन को लेकर गंभीर चिंताएं बनी हुई थीं। अब राज्य सरकार के इस फैसले को इन समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

हम आपको बता दें कि भारत बांग्लादेश सीमा पर लंबे समय तक सीमावर्ती जमीन सीमा सुरक्षा बल को नहीं दिये जाने के कारण कई इलाकों में बाइबंदी अधूरी रही, जिसका फायदा अवैध घुसपैठियों, तस्करीं और आपराधिक गिरोहों ने उठाया। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा के सैकड़ों किलोमीटर हिस्से में बाइ लगाने का काम भूमि अधिग्रहण और प्रशासनिक अड़चनों के कारण वर्षों तक अटका रहा। इसी वजह से सीमा के अनेक हिस्से खुले और संवेदनशील बने रहे, जहां से अवैध रूप से लोगों की आवाजाही लगातार होती रही। सुरक्षा विशेषज्ञों ने बार बार चेतावनी दी कि खुली सीमा का उपयोग केवल अवैध प्रवास के लिए ही नहीं बल्कि पशु



तस्करी, नकली मुद्रा, मानव तस्करी और कट्टरपंथी नेटवर्क द्वारा भी किया जा रहा है। कई सीमावर्ती गांवों के लोगों ने भी बिना बाड़ वाले इलाकों में लगातार घुसपैठ और असुरक्षा का भय व्यक्त किया है।

इस बढ़ती घुसपैठ का असर भारत की आंतरिक सुरक्षा, जनसांख्यिक संतुलन और आर्थिक व्यवस्था पर पड़ा। सीमावर्ती राज्यों में अवैध बस्तियों के विस्तार, फर्जी पहचान पत्रों के नेटवर्क और तस्करी से जुड़ी गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई। कई बार सीमा पार से अपराधियों और घुसपैठियों के हमलों में सीमा सुरक्षा बल के जवानों तथा स्थानीय नागरिकों को भी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि अधूरी बाइबंदी के कारण सीमा पर तनाव और हिंसक घटनाएं बढ़ीं, जिससे भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी असर पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते पूरी जमीन सीमा सुरक्षा

बल को सौंप दी जाती और बाइबंदी पूरी हो जाती, तो अवैध घुसपैठ और उससे जुड़ी आपराधिक गतिविधियों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता था।

इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों को राज्य लोक निर्माण विभाग से हटाकर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपने का निर्णय लिया है। इन सात में से पांच सड़कें सीधे चिकन्स नेक गलियारे से होकर गुजरती हैं। इनमें सेवोक कालिम्पोंग सिक्किम सीमा मार्ग, सिलीगुड़ी कुर्सियांग दार्जिलिंग मार्ग, हासीमारा जयगांव भूटान सीमा मार्ग तथा चांगराबांधा बांग्लादेश सीमा मार्ग जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण रास्ते शामिल हैं।

इन मार्गों का महत्व केवल सामान्य यातायात तक सीमित नहीं है, बल्कि यह क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन, सैन्य रसद और सीमावर्ती राज्यों की आपूर्ति व्यवस्था के लिए भी जीवनरेखा माने जाते हैं। विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 10, जो सिक्किम को जोड़ता है और राष्ट्रीय राजमार्ग 110, जो दार्जिलिंग तक पहुंच प्रदान करता है, लंबे समय से भूस्खलन, भारी वर्षा और सड़क क्षति जैसी समस्याओं से

ब्रिक्स में सटीक रहा भारत का पक्ष

सुरेंद्र कुमार

वर्तमान में, 10 सदस्यों और दस साझेदार देशों वाला ब्रिक्स दुनिया की लगभग 49 फीसदी आबादी, 39 फीसदी वैश्विक जीडीपी और 25 फीसदी वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। विगत 14 मई को, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अध्यक्ष के तौर पर, दिल्ली में हुई ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने आज की जटिल और अनिश्चित दुनिया में विचारों के आदान-प्रदान और आपसी सहमति बनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उभरते बाजारों और विकासशील देशों की ब्रिक्स से यह अपेक्षा है कि वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उथल-पुथल, अभी चल रहे संघर्षों, आर्थिक अनिश्चिताओं तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के इस दौर में एक स्थिर और रचनात्मक भूमिका निभाए। उन्होंने ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, वित्त तक पहुंच, स्वास्थ्य सुरक्षा और बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं के संबंध में कई देशों की कठिनाइयों की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने आर्थिक सुदृढ़ता, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं, विविध बाजारों, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का समर्थन किया। जयशंकर ने एक अधिक स्थिर, न्यायसंगत और समावेशी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए जोरदार अपील की, और एकतरफा तथा जबरदस्ती वाले उपायों व प्रतिबंधों की बढ़ती घटनाओं का कड़ा विरोध किया। ये उपाय अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप नहीं थे। हालांकि अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने, नागरिकों की सुरक्षा करने और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निशाना न बनाने की उनकी अपील नेक इरादों वाली है, पर यूक्रेन, गाजा और लेबनान में जो कुछ हो रहा है (और ईरान में जो हुआ) वह इन भावनाओं के बिल्कुल विपरीत है। इसी तरह, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता स्पष्ट है, पर असल सुधार अब भी दूर की कौड़ी बने हुए हैं। उन्होंने वैश्विक व्यवस्था के लिए संवाद और कूटनीति के महत्व, तथा शांति और सुरक्षा की अहमियत पर उचित ही

जोर दिया; लेकिन क्या इस बात को मानने वाले ज्यादा लोग हैं? विदेश मंत्री जयशंकर ने दृढ़ता से कहा कि होमुंज जलडमरूमध्य और लाल सागर सहित अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के जरिये सुरक्षित समुद्री आवाजाही वैश्विक आर्थिक कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। होमुंज खोलने की मांग को दुनिया भर से समर्थन मिला है, लेकिन अगर ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकेबंदी जारी रहती है, तो किसी भी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं है। यह एक ऐसे देश को सजा देने जैसा है, जिस पर संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए हमला किया गया है। भारत द्वारा जन-केंद्रित और समग्र स्वास्थ्य सेवा की वकालत (जिसमें संक्रामक और गैर-संक्रामक बीमारियों जैसी गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों के मહેनजर सहयोग पर जोर दिया गया है) सौ से अधिक देशों को कोविड वैक्सीन और स्वास्थ्य देखभाल उपकरण उपलब्ध कराने का उसका रिकॉर्ड, और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा डिजिटल भुगतान प्रणाली में अपनी विशेषज्ञता साझा करने की उसकी तत्परता, ग्लोबल साउथ के एक अग्रणी देश के लिए सर्वथा उपयुक्त है। हालांकि भारतीय थीम के व्यापक उद्देश्य सराहनीय और आगे बढ़ाने लायक हैं, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री अराघाची की मांग और यूएई की मांग में तालमेल बिठाना मुश्किल है। गौरतलब है कि अराघाची ने इस्त्राइल और अमेरिका द्वारा अपने देश के खिलाफ की गई खुली आक्रामकता की स्पष्ट निंदा करने की मांग की है, जबकि यूएई ने अपने देश पर ईरान के हमलों की निंदा करने की मांग की है। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि सीमा पार आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। हमारे लिए, पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है, जो लोग उसके साथ नजदीकी बढ़ाते हैं, वे आतंकवाद से लड़ने के अपने संकल्प की कमी को ही दर्शाते हैं। गाजा में मानवीय संकट और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में एक विश्वसनीय मार्ग की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाने हुए, जयशंकर ने दो-राष्ट्र समाधान के प्रति भारत के समर्थन को दोहराया।

पश्चिम बंगाल में काली के पुजारियों का भत्ता बंद

सनत जैन

पश्चिम बंगाल की सरकार के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रिमंडल की बैठक में पश्चिम बंगाल के इमाम और पुजारियों को जो भत्ता ममता सरकार द्वारा दिया जा रहा था, 1 जून 2026 से दोनों के भत्ते बंद करने का निर्णय किया है। इस निर्णय की पश्चिम बंगाल में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। टीएमसी के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी साल मार्च माह से धार्मिक नेताओं के भत्ते में 500 रूपये प्रतिमाह की वृद्धि की थी। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों के इमाम को यह महीने 3000 रूपये तथा पुजारियों को 2000 रूपये की मदद दी जा रही थी। भाजपा की सरकार ने अब यह मानदेय बंद करने का निर्णय लिया है। इसका असर संपूर्ण पश्चिम बंगाल में हिन्दू-मुस्लिम के बीच होना तय है। पश्चिम बंगाल में काली की पूजा होती है।

पश्चिम बंगाल में पूजा में बली और खाने-पीने में मांसाहार का बड़ा उपयोग होता है। बंगाल में हजारों की संख्या में पुजारियों को यह मानदेय मिल रहा था। पुजारियों को आशा थी, नई सरकार इमाम और मुअज्जीन का भत्ता बंद करेगी। हिंदू पुजारियों को 3000 रूपये महीने का मानदेय देने का निर्णय करेगी। सरकार ने दोनों समुदाओं के धार्मिक गुरुओं का भत्ता बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल से जो खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को दो अलगा-अलग भागों में बांटा जा रहा है। हजारों वर्ष पूर्व हिंदुओं में वैष्णव और शैव शाक के बीच में विवाद होते रहे हैं। हिन्दू समुदाय तीन भागों में बंटे हुए थे। शुभेंदु सरकार ने पश्चिम बंगाल में इसी विवाद को फिर से खड़ा कर दिया है।

भाजपा ने पश्चिम बंगाल का चुनाव हिंदुओं के नाम पर लड़ा है। हिंदू पुजारियों को आशा थी, उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। सरकार ने बढ़ाने के स्थान पर



बंद कर दिया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के उद्घोष के साथ वहां पहुंची है। बड़ी संख्या में उत्तर भारत के लोग पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। सरकार के इस निर्णय से बंगाली पुजारियों में जबरदस्त नाराजी देखने को मिल रही है। उनका मानना है वह शाक भक्त हैं, मां काली की पूजा करते हैं। काली की तांत्रिक पूजा अलग तरह की होती है, जिसे वैष्णव और शैव स्वीकार नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की सरकार बनने के बाद सरकार, पश्चिम बंगाल के पुजारियों के साथ हिन्दुओं में जो भेदभाव कर रही है। उससे यह धारणा बन रही है, पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी की सरकार हिंदुओं को हिंदुओं के बीच में बांटने का काम कर रही है।

पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। प्रारंभ में ही यदि इस तरह के भेदभाव की भावना हिंदुओं के बीच में जागृत होती है, तो यह हिंदू एकता को लेकर भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। चुनाव प्रचार के दौरान यह मामला कहीं ना कहीं सामने आया था। उत्तर भारत के जो नेता पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार में गए थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मांस और मछली खाकर यह विश्वास दिलाया था, वह बंगाल की संस्कृति और बंगाल की धार्मिक परंपरा के साथ कोई अन्याय नहीं

इसमें कोई दो राय नहीं कि चिकन्स नेक गलियारा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र की सुरक्षा और संपर्क व्यवस्था मजबूत होना बेहद आवश्यक है। ऐसे में सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरण और राष्ट्रीय राजमार्गों का केंद्रीकृत विकास आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की सामरिक क्षमता को नई मजबूती प्रदान कर सकता है।

बहरहाल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ती घुसपैठ, अधूरी बाइबंदी और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा को प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। पार्टी लगातार आरोप लगाती रही कि पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार की उदासीनता के कारण सीमा सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव वर्षों तक लंबित पड़े रहे। अब राज्य में सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी द्वारा सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों के विकास को मंजूरी देने के फैसले को चुनावी वादों को पूरा करने के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस निर्णय के जरिये राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमाओं की मजबूती उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

ट्रंप के चीन दौर से वैश्विक शांति की उम्मीद

शशांक

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चीन यात्रा पूरी की। इस तरह नौ वर्षों बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन यात्रा हुई। बीते वर्ष अमेरिका द्वारा टैरिफ वार शुरू करने के बाद ट्रंप का चीन दौरा बहुत कुछ संकेत दे रहा है। विदित है कि टैरिफ वार के उस दौर में चीन ने महत्वपूर्ण धातुओं (रेयर अर्थ मिनरल्स) और मैग्नेट्स अमेरिका को न बेचने की बात कही थी, जबकि ट्रंप ने कहा था कि वह चीन को चिप और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण नहीं होने देंगे।

इतना ही नहीं, चीन ने अमेरिका को भेजे जाने वाले कृषि उत्पादों पर भी रोक लगा दी थी। हालांकि दोनों देश इस मामले को सुलझाने की कोशिश भी करते रहे हैं। इसी कारण बीते वर्ष दक्षिण कोरिया के बुसान में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी और उसके बाद दोनों देशों ने टैरिफ को एक वर्ष के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस दौरान अमेरिका ताइवान को 14 अरब डॉलर के हथियारों की भी आपूर्ति करना चाहता था, पर चीन के विरोध के बाद उसने आपूर्ति पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। इन सब उथल-पुथल के बीच ईरान के साथ ट्रंप का युद्ध शुरू हो गया।

ईरान युद्ध से पहले ट्रंप ने वेनेजुएला में दखल दिया और वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, ट्रंप ने यह सब कुछ चीन को दबाने के लिए किया है। चीन का वेनेजुएला के साथ दीर्घावधि का अनुबंध था। वहां का लगभग 80 प्रतिशत तेल चीन को जाता था, जो अमेरिका के दखल के बाद रुक गया। दूसरा, ईरान का लगभग 80 प्रतिशत तेल चीन को जाता था, युद्ध छिड़ने के बाद वह भी रुक गया। वास्तविकता यह है कि जब से अमेरिका का ईरान से युद्ध शुरू हुआ है, तभी से ट्रंप चाहते हैं कि वह ताइवान को हथियार आपूर्ति की बात उठाल कर चीन पर दबाव बनायें।

जाहिर-सी बात है कि चीन नहीं चाहता कि अमेरिका ताइवान को हथियार दे, ऐसे में ट्रंप की मंशा ताइवान को हथियार आपूर्ति में देरी करना और उसके एवज में चीन पर यह दबाव बनाना है कि वह ईरान



को समर्थन देना बंद करे और ईरान युद्ध रुकवाने में ट्रंप की मदद करे। ऐसा लगता है कि ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान इस मामले में कुछ बात बनी है, क्योंकि चीन ने कह दिया है कि हमारी रेड लाइन (लक्ष्मण रेखा) ताइवान है और अमेरिका ने कहा है कि उसकी रेड लाइन ईरान है। जाहिर है कि ईरान जिस तरीके से होमुंज को नियंत्रित कर रहा है, नौवहन पर रोक लगा रखी है, वह ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा।

उथल-पुथल भरे इस वैश्विक परिदृश्य में यदि चीन और अमेरिका के बीच यह समझौता हो जाता है कि चीन ईरान को मदद नहीं देगा और ईरान से पहले जो तेल ले रहा था, वह अमेरिका से लेगा, तो यह चीन के लिए राहत की बात होगी। चीन ने तो यह कोशिश भी शुरू कर दी है। वर्तमान में वह अमेरिका से छह सौ हजार (छह लाख) बैरल तेल प्रतिदिन ले रहा है। इस तरह कहा जा सकता है कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच हुई हालिया मुलाकात कहीं न कहीं जी-2 की तरफ बढ़ने का प्रयास है, जहां विश्व की दो बड़ी शक्तियां आपस में ऐसे संबंध बनाकर रखें, जिसमें उनकी अपनी प्राथमिकताएं पूरी होती रहें।

देखा जाये, तो आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के बीच काफी वर्षों से बातचीत चल रही है। इसके प्रमुख कारणों में एक एआइ कतरीक भी है। एआइ के क्षेत्र में चीन जहां बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है, वहीं अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के पास एआइ के क्षेत्र में कम से कम तीन ऐसी तकनीकें हैं, जिनके आसपास चीन समेत कोई भी देश नहीं है। एनवीडिया इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है। यही कारण है कि ट्रंप के चीन दौरे

पर उसके साथ एनवीडिया के सीइओ भी गये थे।

इससे लग रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका से चीन को तकनीक का हस्तांतरण हो जाये और चीन से रेयर अर्थ मिनरल्स और मैग्नेट्स अमेरिका को मिलता रहे। इतना ही नहीं, अमेरिका चीन को अपने कृषि उत्पाद- गेहूं, सोयाबीन आदि- भी बेचना चाहता है, ये चीजें चीन को चाहिए थीं। यदि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार आता है, तो एशिया में तनाव की जो स्थिति फिर से बन रही है, उससे थोड़े समय के लिए राहत मिलेगी। लेकिन हमारी सारी परेशानियां दूर नहीं होंगी, क्योंकि होमुंज जलडमरूमध्य में अब भी तनाव बने रहने की उम्मीद है। यहां भारत को सावधानी बरतने की जरूरत है।

चीन-अमेरिका के संबंध प्रगाढ़ होने पर हो सकता है कि अमेरिका भारत को दरकिनार कर दे। ऐसी स्थिति आए, उससे पहले भारत को यूरोप के उन देशों के साथ, जो पहले अमेरिका के सहयोगी थे, अपने संबंध मजबूत करने चाहिए। अपनी ऊर्जा सुरक्षा की मजबूती की दिशा में कदम उठाना चाहिए। तेल-गैस के वैकल्पिक स्रोत तैयार रखने चाहिए और देश के आत्मनिर्भरता अभियान को भी आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आज जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, वे भविष्य में उत्पन्न न हों। अपने जिन संसाधनों को हम बचा सकते हैं, उन्हें बचाने की जरूरत है। यहां विश्व की बात करनी भी जरूरी है, क्योंकि भारत वर्तमान में ब्रिक्स का अध्यक्ष है और चीन, रूस समेत ईरान और यूएइ इसके सदस्य हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि ब्रिक्स को मजबूत बनाकर रखा जाए और अमेरिका को मानाया जाए, ताकि ईरान युद्ध समाप्त हो और होमुंज से निर्बाध आवाजाही शुरू हो सके। यहां चीन और रूस की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि दोनों ईरान के सहयोगी रहे हैं और उन्हीं के समर्थन के कारण ईरान इतना बढ़-चढ़कर बोल रहा है। दोनों देश यदि ईरान को समझाने में सफल हो जाते हैं, तो यह युद्ध समाप्त हो सकता है और पश्चिम एशिया तथा खाड़ी में शांति स्थापित हो सकती है। ट्रंप-पूजा के बीच हुई मुलाकात के बाद ट्रंप को यह शह नहीं मिलनी चाहिए कि वह ईरान के ऊपर परमाणु हमला कर दे।

क्षमा शर्मा

हाल ही में मशहूर अभिनेता विजय थलपति ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वहां वंदे मातरम गाया गया। उनकी एक विधायक और अभी तक विजय की कैबिनेट की इक्लौती महिला मंत्री, एस. कीर्तना ने कहा कि मैं हिंदी में बात कर रही हूं। मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व हर जगह, पूरे भारत में, यहां तक कि दूसरे देशों में फैलाना चाहती हूं, इसीलिए इक्षहदी में बात कर रही हूं। तमिलनाडु में अब तक द्रमुक सत्ता में थी। उसका हिंदी विरोध मशहूर है। हिंदी का विरोध करते-करते वे हिंदी भाषियों को जब चाहे तब कूट देते थे। एक बार उन्होंने इक्षहदी बोलने वालों को गोलगप्पे बेचने वाला कहा था। जैसे कि गोलगप्पे बेचकर रोटी-रोजी कमाना कितनी गलत बात है और वे आदमी ही नहीं होते। बहुत पहले चेन्नई गई थी। तब इसे मद्रास नाम से जाना जाता था। वहां लोग इक्षहदी में बात करते ही नफरती नजरों से देखते थे। जैसे हिंदी बोलना कितना बड़ा अपराध हो। यही नहीं, ऑटो, टैक्सी वाले हिंदी में बोलने पर उतारने की धमकी देते थे। होटलों तक में आप हिंदी बोलकर खाना नहीं मंगा सकते थे। मुश्किल यह थी कि तमिल आती नहीं और अंग्रेजी बहुत से लोग समझते नहीं थे। इसलिए तय किया कि अब वहां कभी नहीं जाना है। जहां एक भाषा बोलने पर आप से किसी शत्रु देश से आए की तरह व्यवहार किया जाए, तो क्या फायदा। राजनीतिक दल अपने-अपने स्वार्थ के लिए आम लोगों में कितने वैमनस्य के बीज बोते हैं, यह इस बात का उदाहरण है। लेकिन राजनीतिक दलों से इतर आम लोगों के जीवन में कुछ और ही दिखाई देता है। बहुत-सी दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियां, जब हिंदी फिल्मों में आईं, तभी उन्हें अखिल भारतीय ख्याति मिली। इसे समय-समय पर दिग् गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकारा भी। कमल हासन ने ‘एक दूजे के लिए’ फिल्म में काम किया था, जो सुपरहिट रही थी। वह हिंदी क्षेत्र में घर-घर का नाम बन गए थे। लेकिन इन दिनों वह अपने तीखे हिंदी विरोध के लिए जाने जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और अपने समय की मशहूर अभिनेत्री जयललिता ने तो एक हिंदी गाना भी गाया था। उनकी आवाज भी बहुत मधुर थी। बहुत से दक्षिण भारतीय लेखक निजी बातचीत में इस लेखिका से कह चुके हैं कि वे चाहते हैं कि उनकी रचनाओं का अनुवाद हिंदी में हो। एस. कीर्तना के बयान से जाहिर है कि वह विजय थलपति के विचारों को ही व्यक्त कर रही हैं। यानी कि उन्हें पता है कि

तमिलनाडु का बदलता परिदृश्य

अगर भारत भर में उनकी पार्टी को जगह बनानी है, तो उन्हें स्वीकार्यता चाहिए। वे हिंदी क्षेत्र को नकार कर सफल नहीं हो सकते। साथ ही, वे द्रमुक के हिंदी विरोध से अपने को अलग दिखाना भी चाहते हैं। वंदे मातरम को जगह देकर यह भी बताया गया कि वे भाजपा की भूमि पर भी सेंध लगाना चाहते हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक बार बंगाल की प्रख्यात लेखिका महाश्वेता देवी ने कहा था कि जब उनकी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद हुआ, तभी उन्हें बड़ा पाठक वर्ग मिला। एक निजी अनुभव भी सांझा कर रही हूं। मेरी घरेलू सहायिका तमिल है। उसकी बेटी ने दिल्ली से 12वीं पास की। फिर उसका विवाह तमिलनाडु के एक गांव में हो गया। वहां जाते ही उसे एक स्कूल में 10 हजार रुपए की नौकरी मिल गई। उसे हिंदी पढ़ाने का काम मिला। इस तरफ मात्र 12वीं पास को शायद ही 10 हजार रुपए की नौकरी किसी स्कूल में मिलती, लेकिन वहां यह हुआ। यानी कि वहां आम लोग अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। कारण कि वे इस तरफ आकर कोई रोजगार पा सकें। उन्हें भाषाई दिक्रत का सामना न करना पड़े। बल्कि कुछ साल पहले द्रमुक की भी अपना एक चुनावी पम्पलैट हिंदी में छपवाया था। उनके एक नेता को एक बार टी.वी. पर हिंदी बोलते भी देखा गया था। हिंदी क्षेत्र में शायद ही आपने ऐसा सुना होगा कि किसी को भाषा के नाम पर सताया गया हो, खदेड़ा गया हो या काम न दिया गया हो। आज भी बहुत से कर्मचारी दक्षिण भारतीय हैं लेकिन शायद ही उन्हें कोई सतताता है। न उनके खान-पान के बारे में कोई नकारात्मक बात होती है बल्कि दक्षिण का इडली, डोसा, सांभर, रसम, बीसे बेले बात आदि उत्तर भारतीयों में बहुत लोकप्रिय हैं। एक बात और न जाने क्यों दक्षिण भारत में लोग समझते हैं कि एक अभिनेता फिल्मों में जो क्रांति करता है, वह जीवन और राजनीति में भी कर सकता है। इसीलिए वे उन्हें चुनाव जिता देते हैं। उनके जबरदस्त फैन होते हैं। बार-बार उन्हें गद्दी सौंपते हैं। किसी की लम्बी उम्र के लिए अंगारों पर चलते हैं। उनके लिए मंदिर बनाते हैं। यदि किसी की मृत्यु हो जाए, तो जान तक दे देते हैं। जबकि हिंदी क्षेत्र में ऐसा दिखाई नहीं देता। बड़े से बड़े अभिनेता, चाहे वह अमिताभ बच्चन हों, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, धर्मेद या हेमा मालिनी, उन्हें सिर पर नहीं बिठाते। उनके लिए जान न्यौछावर नहीं करते। इस इलाके में शायद ही कोई अभिनेता कभी मुख्यमंत्री बना हो। इसीलिए इनमें से अधिकांश अभिनेता राजनीति में सफल नहीं रहे हैं।

इन तीन कारणों से होते हैं सबसे ज्यादा तलाक़ शादी बचाने के लिए जान लें कपल

भारतीय समाज में शादी बेहद अहम और खूबसूरत रिश्ता होता है जिसे जन्मों- जन्मों के बंधन के रूप में हमारी संस्कृति में शामिल किया गया है। हालांकि आज के दौर में कपल्स के बीच अलगाव के मामले तेजी से बढ़े हैं। डिवोर्स या तलाक होना सामान्य होता जा रहा है। कई बार कुछ गलतफहमियों, बिगड़ी परिस्थितियों से रिश्ता कमजोर हो जाता है और युगल एक दूसरे से दूर जाने का फैसला ले लेते हैं।

नए युगलों या युवा कपल्स के बीच एक दूसरे को नासमझना आम बात है लेकिन इस दौर में कई ऐसे कपल अलग हो रहे हैं जो कि सालों तक साथ रहे हों। सालों साथ रहने के बाद भी ऐसा क्या है जो उन्हें तलाक लेने के लिए मजबूर कर देता है। यानी शादी न निभा पाने के सबसे सामान्य कारण क्या होते हैं, जिसके कारण पति-पत्नी अपने जन्मों का रिश्ता इसी जन्म में खत्म करके अलग हो जाते हैं। आज के दौर में तलाक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके पीछे कुछ खास वजहें होती हैं। अगर कपल इन कारणों को पहले से समझ लें और समय रहते इन पर काम करें, तो अपनी शादीशुदा जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आइए जानते हैं तलाक के तीन सबसे बड़े कारण और उन्हें रोकने के



उपाय।

भरोसा और वफादारी की कमी
सबसे अधिक शादी टूटने की वजह बेवफाई होती है। शादी के बाद एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर पति-पत्नी को एक दूसरे से दूर कर सकता है। झूठ बोलना, बातें छुपाना, सोशल मीडिया और बाहरी लोगों पर ज्यादा ध्यान देने से कपल एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। जहां भरोसा नहीं, वहां रिश्ता कैसे? इसी विचार के साथ लोग अपने पार्टनर से दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं और पहुंच जाते हैं कोर्ट, सात वचनों और फेरों को रिवर्स करने। अगर आप नहीं चाहते कि आपका रिश्ता तलाक की अर्जियों तक पहुंचे तो अपने रिश्ते और पार्टनर से ईमानदारी बनाए रखें। पार्टनर संग भरोसे को मजबूत बनाने के लिए रिश्ते में पारदर्शिता लाएं। अगर किसी बात से परेशानी

है तो उसे खुलकर कहें, छुपाएं नहीं।

आर्थिक परेशानियां
बड़े-बूढ़ों को कहावत है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत सिर्फ बाप-भाई पर नहीं, बल्कि पति-पत्नी पर भी लागू होने लगी है। इस दौर में पैसों और आर्थिक परेशानियों को लेकर विवाद तलाक तक पहुंचने लगा है। कपल पैसे को लेकर बहस करते हैं या असहमति जताते हैं। उनकी खर्च करने की आदतों में बड़ा अंतर, या आर्थिक जिम्मेदारियों को ठीक से न निभा पाने के कारण उनके बीच अलगाव की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। पैसों की तंगी अच्छे रिश्ते पर भी दबाव डालती है और शादी में तनाव व दिक्कत शुरू हो जाती हैं। अब अगर आपको नहीं चाहिए कि पैसा आपके रिश्ते को काला

नाग बनकर डसे, तो पार्टनर संग पैसे से जुड़े मामलों पर खुलकर चर्चा करें और मिलकर निर्णय लें। वित्तीय या आर्थिक योजनाएं बनाएं और जरूरतों को प्राथमिकता दें। बजट बनाकर काम करें, बेवजह के खर्चों से बचें।

संवाद
किसी भी रिश्ते में अलगाव का सबसे सामान्य कारण संवाद होता है। बातचीत होती ही नहीं तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। हर रिश्ते में मनमुटाव, समझ की कमी, गलतफहमियां होना स्वाभाविक है लेकिन संवाद के जरिए इन चीजों को दूर किया जा सकता है। लेकिन जब पति-पत्नी खुलकर बातचीत ही नहीं करते तो उनका रिश्ता छोटी सी समस्या आने पर ही डोल जाता है। समस्याओं पर चर्चा करने के बजाय चुप रहना या झगड़ना दूरियां बढ़ाता है। इसका एक नुकसान ये भी है कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझ नहीं पाते और न ही उन्हें आपकी समझने का मौका देते हैं। आपको चुप्पी रिश्ते में जहर की तरह न खुल जाए, इसके लिए अपने पार्टनर से खुलकर भावनाओं की अभिव्यक्ति करें। झगड़े के दौरान भी संवाद बनाए रखें और एक-दूसरे को सुनें। कोई गलतफहमी है तो उसे बातचीत से हल करें ना कि बातें इग्नोर करें।



शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों और दो अलग-अलग सोच का मिलन होती है। नई-नई शादी के बाद हर कपल अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार अनजाने में कही गई कुछ बातें रिश्ते में खटास पैदा कर सकती हैं। शुरुआत के दिनों में पार्टनर एक-दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए इस दौरान बातचीत का तरीका बेहद मायने रखता है। कई लोग मजाक-मजाक में ऐसी बातें कह देते हैं जो सामने वाले को बुरी लग सकती हैं। बार-बार तुलना करना, पुरानी बातों को छेड़ना या छोटी-छोटी बातों पर शिकायत करना रिश्ते

को कमजोर बना सकता है। शादी के शुरुआती दिनों में भरोसा, सम्मान और समझदारी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता लंबे समय तक प्यार और विश्वास से भरा रहे, तो कुछ बातों को कहने से बचना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि शादी के तुरंत बाद अपने पार्टनर से कौन-सी बातें नहीं करनी चाहिए ताकि रिश्ते में प्यार और मिठास बनी रहे।

एक्स पार्टनर की बातें करने से बचें
नई शादी के बाद पुराने रिश्तों का जिक्र करना कई बार पार्टनर को असहज महसूस करा सकता है। बार-बार एक्स पार्टनर की

को कमजोर बना सकता है। शादी के शुरुआती दिनों में भरोसा, सम्मान और समझदारी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता लंबे समय तक प्यार और विश्वास से भरा रहे, तो कुछ बातों को कहने से बचना बेहद जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि शादी के तुरंत बाद अपने पार्टनर से कौन-सी बातें नहीं करनी चाहिए ताकि रिश्ते में प्यार और मिठास बनी रहे।

एक्स पार्टनर की बातें करने से बचें
नई शादी के बाद पुराने रिश्तों का जिक्र करना कई बार पार्टनर को असहज महसूस करा सकता है। बार-बार एक्स पार्टनर की

तुलना करना या पुरानी यादें शेयर करना रिश्ते में insecurity बढ़ा सकता है। बेहतर होगा कि आप अपने वर्तमान रिश्ते पर फोकस करें।

परिवार को लेकर न करें कटाक्ष
शादी के बाद दोनों परिवारों का सम्मान करना बेहद जरूरी होता है। पार्टनर के परिवार के बारे में गलत बातें कहना या मजाक उड़ाना रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। अगर कोई बात पसंद नहीं भी आती, तो उसे शांत तरीके से समझाने की कोशिश करें।

हर सगया शिकायत करना पड़ सकता है भारी
अगर आप छोटी-छोटी बातों पर लगातार शिकायत करते हैं, तो इससे रिश्ते में नकारात्मकता बढ़ सकती है। नई शादी में एक-दूसरे की आदतों को समझने में समय लगता है। इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी है।

दूसरों से तुलना करने की गलती न करें
अपने पार्टनर की तुलना किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया कपल से करना रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है। हर इंसान और हर रिश्ता अलग होता है। तुलना करने से आत्मविश्वास कम होता है और मनमुटाव बढ़ सकता है।

रिश्ते में स्पेस देना भी है जरूरी
शादी के बाद हर समय सवाल-जवाब या जरूरत से ज्यादा रोक-टोक पार्टनर को परेशान कर सकती है। रिश्ते में प्यार के साथ-साथ personal space भी जरूरी होता है। एक-दूसरे पर भरोसा रखना रिश्ते को मजबूत बनाता है।

महिलाओं की इन आदतों से आकर्षित होते हैं पुरुष, कई तो हार बैठते हैं दिल

सही हेल्मेट चुनते समय ध्यान रखें ये जरूरी बातें

रफ्तार के शौकीनों के लिए बाइक की सवारी करना जितना रोमांचक होता है, यह उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है। इसलिए बाइक राइडर को किसी दुर्घटना की स्थिति में निपटने के लिए ज्यादा बचाव की जरूरत होती है। आमतौर पर लोग हेल्मेट इसलिए पहनते हैं ताकि वो पुलिस की कार्रवाई और चालान से बच सकें। लेकिन यह धारणा गलत है। हेल्मेट बाइक राइडर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ज्यादातर दुर्घटनाओं में देखा गया है कि हेल्मेट नहीं लगाने के नतीजे ज्यादा गंभीर होते हैं। इसलिए सरकार ने बाइक राइडर के साथ पीछे बैठने वाले सवार के लिए भी हेल्मेट लगाना अनिवार्य कर रखा है।

ऐसा देखा गया है कि कई बार लोग हेल्मेट पहनने में असहज महसूस करते हैं। या उन्हें लगता है कि हेल्मेट के साथ वे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए एक हेल्मेट की तलाश में हैं। तो यहां हम आपको बता रहे हैं, कि हेल्मेट खरीदते समय आपको किन जरूरी बातों को ध्यान रखना चाहिए।

हेल्मेट की त्वालिटी चेक करें
नया हेल्मेट खरीदते समय सबसे पहले सुरक्षा मानकों की जांच करनी चाहिए। हेल्मेट इस पर ISI मार्क



होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हेल्मेट अच्छी क्वालिटी का है। हेल्मेट खरीदते समय उसकी फिटिंग चेक करना भी बहुत जरूरी है। आपको ऐसा हेल्मेट चुनना चाहिए जो आपके सिर पर अच्छी तरह फिट बैठता हो। साथ ही आरामदायक भी हो। हेल्मेट में एंटी-फॉग फीचर होना चाहिए। क्योंकि यह राइडिंग के दौरान आपके सिर को कूल रखेगा।

अच्छी विजिबिलिटी जरूरी
बाइक की सुरक्षित ड्राइविंग के लिए हेल्मेट की अच्छी विजिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए वाइजर अच्छी क्वालिटी का होना

चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए कि आप काले रंग के वाइजर वाला हेल्मेट न खरीदें। दरअसल काले रंग के वाइजर से रात में बाइक चलाने के दौरान काफी दिक्कत हो सकती है। जबकि नॉर्मल वाइजर से किसी भी समय विजिबिलिटी की दिक्कत नहीं होगी। हेल्मेट में अगर एंटी-फॉग फीचर हो तो धुंध के समय दोपहिया वाहन चलाना आसान हो जाता है।

हेल्मेट वजन में होना चाहिए हल्का
हेल्मेट का वजन बहुत मायने रखता है। आपको ऐसा हेल्मेट चुनना चाहिए जो आपको पहने के बाद सिर पर ज्यादा भारी न लगे।

बाजार में फुल फेस और हाफ फेस हेल्मेट दोनों उपलब्ध हैं। कई लोग ज्यादा हवा लगने के लिए हास फेस हेल्मेट का चुनाव करते हैं। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से फुल फेस हेल्मेट खरीदना ज्यादा सही होता है।

स्पोर्ट्स बाइक के लिए हेल्मेट
अगर आप स्पोर्ट्स बाइक चलाने के शौकीन हैं तो आपको इसके लिए ट्रैक डे हेल्मेट खरीदना चाहिए। यह आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। ये एक फुल फेस हेल्मेट है, जो ज्यादा सुरक्षा देता है। इन हेल्मेट में सबसे ऊपर एयर वेंट्स होते हैं, जिनसे हवा को अंदर और बाहर होती है। इसकी कीमत रेगुलर हेल्मेट की तुलना से थोड़ी ज्यादा होती है, पर ये हेल्मेट बेहतर सुरक्षा देते हैं।

एडवेंचर बाइक राइडिंग के दौरान के लिए एडोबी हेल्मेट एक मॉड्यूलर मोटोक्रांस हेल्मेट बेहतर साबित हो सकता है। इसके आलावा कंफर्ट के लिए कुछ हेल्मेट में एक्स्ट्रा पैडिंग भी दी जाती है। दुर्घटना के दौरान इन हेल्मेट में आपका सिर सेफ पोजिशन में रहता है, जो आपको चोट से बचाता है। वहीं हल्की प्लास्टिक के वाइजर वाले हेल्मेट आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।

अदाओं का जिक्र हो तो महिलाओं का नाम आना लाजमी है। लेकिन इसी अदा पर फिदा हो जाने वाले पुरुषों का जिक्र भी जरूरी है। यह फिल्मी डायलॉग तो सुना ही होगा?

इसी अदा पर तो दिल हार बैठे हैं...
सवाल है कि आखिर किस अदा पर लोग फिदा हो जाते हैं? हर पुरुष की पसंद अलग-अलग हो सकती है लेकिन महिलाओं की कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो ज्यादातर पुरुषों को आकर्षित करती हैं। महिलाओं की ये आदतें सिर्फ बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, व्यवहार और सोच से जुड़ी होती हैं। बाहरी सुंदरता तो कुछ समय के लिए ही आकर्षित करती हैं लेकिन असली खूबसूरती स्वभाव, आत्मविश्वास और सोच में होती है। आइए जानते हैं महिलाओं की उन आदतों या अदाओं के बारे में जो ज्यादातर पुरुषों को इम्प्रेस करती हैं।

विनम्रता और सकारात्मकता
ऐसी महिलाएं जो दूसरों से अच्छा व्यवहार करती हैं, मुस्कुराकर बात करती हैं और उनके व्यवहार में विनम्रता का भाव होता है, वह पुरुषों को काफी

आकर्षित करती हैं। जीवन को लेकर महिलाओं का सकारात्मक नजरिया, मुश्किल समय में उनका सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि दिमाग और समझदारी भी बेहद मायने रखती है। पुरुष ऐसी

सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि दिमाग और समझदारी भी बेहद मायने रखती है। पुरुष ऐसी

भी सम्मान करते हैं।

आत्मनिर्भरता और सेल्फ केयर
ऐसे महिलाएं जो अपने फैसले लेने में सक्षम हों, दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर हों और जीवन को अपने तरीके से जीने में सक्षम हों, वह पुरुषों को पसंद आती हैं। आत्मनिर्भरता एक मजबूत व्यक्तित्व की निशानी है। इसके अलावा जो महिला खुद की केयर करना जानती है, उसे पुरुषों की केयर भी मिलती है। महंगे कपड़े पहनना, घंटों मेकअप करना सेल्फ केयर नहीं, बल्कि खुद को अच्छे से संवराना, फिट रहना और सेहत पर ध्यान देने वाली महिलाएं पुरुषों को इंप्रेस करती हैं।

सपोर्ट करने वाली महिला
पुरुष हमेशा ऐसी महिलाओं से आकर्षित होते हैं जो उन्हें प्रेरित करें। उनके सपनों को समझे और मुश्किल समय में उनका हासला बढ़ाएं। दूसरों की मदद करने वाली महिला भी पुरुषों को पसंद होती हैं। दूसरों की केयर करने वाली , परिवार और दोस्तों के प्रति लगाव रखने वाली और जरूरत पर मदद करने वाली महिला हर किसी को प्रभावित करती हैं।

हर मां अपनी बेटी को जरूर दे ये एक सीख ताकि वो हर मुश्किल में रहे मजबूत

दूसरों की खुशी के लिए खुद से बेईमानी न करें अपने वजूद को बचाएं और अभी बदल लें ये आदतें

कई बार हम दूसरों को खुश करने या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के चक्कर में खुद को ही भूल जाते हैं। उनकी पसंद-नापसंद के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में हम अपनी पहचान और आत्मसम्मान से समझौता कर बैठते हैं। सच तो ये है कि जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं, वे आपको आपके असली रूप में ही स्वीकार करेंगे। इसलिए, अपनी ये अनमोल आदतें कभी न छोड़ें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।

ईमानदारी
ईमानदारी वो गहना है, जो कभी फीका नहीं पड़ता। सच्चाई से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। अगर आप दूसरों को खुश करने के लिए सच बोलने से कतराते हैं या सच को तोड़-मरोड़कर पेश करते हैं, तो धीरे-धीरे आप अपनी आत्मा से ही दूर हो जाएंगे। खुद से झूठ



बोलना सबसे बड़ा अपराध होता है। इसलिए, किसी भी स्थिति में अपनी ईमानदारी को बनाए रखें।

स्वभिमान
स्वाभिमान ही इंसान की असली ताकत है। अगर कोई आपको इज्जत नहीं करता, तो वहां झुकने

की जरूरत नहीं है। सम्मान पाने के लिए दूसरों की शतों पर मत चलिए। खुद की इज्जत करना सीखिए, तभी दुनिया आपकी इज्जत करेगी।

अपनी सोच और मूल्य
आपकी सोच और मूल्य आपके

व्यक्तित्व की नींव होते हैं। अगर आप दूसरों की राय के अनुसार अपने सिद्धांतों को बदलने लगेंगे, तो अपनी पहचान खो बैठेंगे। अपनी सोच और मूल्यों को बनाए रखें ,चाहे दुनिया कुछ भी कहे।

स्वतंत्रता
आजादी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। किसी भी रिश्ते या परिस्थिति को अपनी आजादी छीनने मत दीजिए। अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें और जो सही लगे, वही करें। जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं, वे आपकी स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे।

करुणा और दयालुता
दयालुता को कमजोरी समझने की गलती मत कीजिए। यह आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। अगर कोई आपको भलमनसाहत का गलत फायदा उठाता है, तो ये उसकी गलती है, आपकी नहीं। दयालु बने रहिए , दुनिया में अच्छाई की हमेशा जरूरत होती है।

हर माता-पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी जिंदगी में सफल, मजबूत और आत्मविश्वासी बने। इसके लिए अच्छी पढ़ाई और संस्कार जरूरी हैं, लेकिन एक ऐसी सीख है जो हर लड़की को अंदर से मजबूत बनाती है और ये सीख है “गलत बात पर बिना डर ‘ना’ कहना।” अक्सर लड़कियां लोगों को खुश रखने के लिए अपनी इच्छाओं और भावनाओं को दबा देती हैं। धीरे-धीरे यही आदत उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है। ऐसे में मां का सबसे बड़ा फर्ज है कि वह बेटी को बचपन से अपनी बात खुलकर रखने और गलत चीजों का विरोध करना सिखाए। जब लड़की ‘ना’ कहना सीख जाती है, तब वह रिश्तों, करियर और समाज में खुद की इज्जत करना भी सीखती है। यही एक आदत उसे मानसिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी



बनाती है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यह सीख किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं होती।

वर्गों जरूरी है बेटियों को ‘ना’ कहना सिखाना?
1. आत्मसम्मान बढ़ता है जब बेटी अपनी पसंद-नापसंद खुलकर बताती है, तब उसे अपनी अहमियत समझ आती है।
2. गलत लोगों से दूरी बनती है हर बात मान लेने की आदत कई

बार लोगों को फायदा उठाने का मौका देती है। ‘ना’ कहना सुरक्षा भी देता है।
3. फैसले लेने का आत्मविश्वास आता है जो लड़की अपनी बात रखने से नहीं डरती, वह जिंदगी के बड़े फैसले भी मजबूती से लेती है।
4. मानसिक दबाव कम होता है हर किसी को खुश रखने की कोशिश तनाव बढ़ाती है। अपनी

सीमाएं तय करना मानसिक शांति देता है।
5. मजबूत व्यक्तित्व बनता है स्पष्ट सोच और खुलकर बोलने वाली लड़कियां समाज में अलग पहचान बनाती हैं।

मां कैसे सिखाए ये आदत?
बेटी की हर बात ध्यान से सुनें उसकी राय को महत्व दें छोटी-छोटी बातों में उसे निर्णय लेने दें
डॉटने के बजाय समझाने की आदत रखें उसे यह महसूस कराएं कि अपनी बात रखना गलत नहीं है हमेशा ध्यान रखें कि बेटी को दिया गया सबसे बड़ा उपहार महंगे कपड़े या सुविधाएं नहीं, बल्कि आत्मविश्वास होता है। अगर मां अपनी बेटी को सही समय पर ‘ना’ कहना सिखा दे, तो वह जिंदगीभर हर परिस्थिति में खुद को मजबूत महसूस करती है।

अगले महीने जी7 सम्मेलन में फ्रांस जाएंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड की अगले महीने मुलाकात हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप फ्रांस में होने वाले जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 15 से 17 जून को होने वाला यह सम्मेलन फ्रांस के एवियन-लेस-बैंस में होगा। 16 महीने से भी ज्यादा वक्त में यह पहली बार होगा जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होगी।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फ्रांस की यात्रा पर जाने वाले हैं। यह शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक होगा। पिछले दिनों इस यात्रा के बारे में पुष्टि करते हुए फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था। इस बयान में विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन-नोएल के बीच हुई बातचीत की मुख्य बातें बताई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक यह बातचीत फ्रांस में जी7 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई थी। फ्रांस की ऑफिशियल रिलीज में कहा गया है कि दोनों मंत्रियों ने इस बात का स्वागत किया कि पीएम मोदी ने एविन शिखर सम्मेलन में अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है।

जनता सड़कों पर आई तो सरकार संभाल नहीं पाएगी

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि देश में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और यदि समय रहते सरकार ने स्थिति नहीं संभाली तो जनता सड़कों पर उतर सकती है। राहुल गांधी बार-बार सरकार को इसलिए चेतावनी दे रहे हैं कि हालात नियंत्रण से बाहर न हो जाएं।जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी राजनीति नहीं करते, बल्कि देशहित में अपनी बात रखते हैं। राहुल गांधी दिल के साफ इंसान हैं और जो बात उन्हें सही लगती है, वह खुलकर कहते हैं। गहलोत के अनुसार राहुल लगातार देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को लेकर सरकार को आगाह कर रहे हैं, ताकि जनता में असंतोष विस्फोटक रूप न ले ले। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन पर भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री ने लोगों को सोना न खरीदने, विदेश यात्रा कम करने और खर्च सीमित रखने जैसी सलाह तो दी।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को 23 मई को आएंगे भारत

नई दिल्ली। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आगामी 23 से 26 मई तक भारत की अपनी पहली चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। इस कूटनीतिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, रक्षा, सुरक्षा तथा ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करना है। विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिपोट के अनुसार, अपने इस चार दिवसीय दौरे के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे, जहां वे वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। इस कूटनीतिक वार्ता के एजेंडे में कई अहम द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दे शामिल हैं। मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण और क्लोन एनर्जी को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा होगी। इसके अतिरिक्त, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को प्रगाढ़ करने, अत्याधुनिक सैन्य सहयोग को बढ़ाने और रक्षा प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण पर भी बात की जाएगी।

इकरा हसन के समर्थन में उतरे अखिलेश बोले- गुनाह तो बताइए?

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद राजनीतिक माहौल पूरी तरह गरमा गया है। सांसद इकरा हसन ने पुलिस प्रशासन पर जबरन थाने में बिठाने और हिरासत में लेने का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने सरकार व पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कैराना से सपा सांसद इकरा हसन जसाला गांव की एक बुजुर्ग महिला के साथ पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) से मिलने पहुंची थीं। महिला के बेटे की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी और वे इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थीं। सांसद का आरोप है कि पीड़ित पक्ष की मांगों को अनसुना कर दिया गया। जब वे कार्यालय के बाहर पार्किंग एरिया में दूसरी अर्जी तैयार कर रही थीं।

अमेरिकी संसद में ईरान जंग रोकने वाला प्रस्ताव पास

तेल अविव/तेहरान/वाशिंगटन। अमेरिकी संसद में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की सैन्य शक्तियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। वोटिंग में 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। हालांकि 3 रिपब्लिकन सांसद वोटिंग में शामिल नहीं हुए। यह प्रस्ताव 50-47 से पास हुआ, हालांकि इसे कानून बनने के लिए अभी कुछ और चरणों से गुजरना होगा। अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो ट्रम्प सरकार को ईरान के खिलाफ युद्ध जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। अभी सीनेट में इस पर अंतिम वोटिंग होनी बाकी है। इसके बाद इसे रिपब्लिकन बहुमत वाली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से मंजूरी लेनी होगी। हालांकि उसके बाद भी ट्रम्प इसके खिलाफ वीटो कर सकते हैं। फिर उस वीटो की रद्द करने के लिए सीनेट और हाउस दोनों में दो-तिहाई बहुमत चाहिए होगा, जो फिलहाल मुश्किल माना जा रहा है। यह वोट विपक्ष के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है जो कह रहे थे कि अमेरिका में युद्ध शुरू करने या सेना भेजने का अधिकार राष्ट्रपति नहीं बल्कि संसद के पास होना चाहिए।

नीट पेपर लीक के कितने गुनाहगार?

एनटीए एक्सपर्ट्स से लेकर ब्यूटीशियन और कंसल्टेंसी तक फैला था नेटवर्क

नईदिल्ली। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र के लातूर से आरसीसी के संचालक शिवराज मोटेगांवकर समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि पेपर लीक का नेटवर्क एनटीए स्टाफ से लेकर बड़े कोचिंग संस्थानों और मेडिकल एडमिशन कंसल्टेंसी तक फैला हुआ था।

सीबीआई नीट-यूजी 2026 पेपर लीक केस की जांच में जुटी है और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है। हर बार एक नई रहस्यमय परत सामने आ रही है। इस मामले में सीबीआई ने अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि पेपर लीक का नेटवर्क एनटीए से लेकर बड़े कोचिंग संस्थानों तक फैला हुआ था। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से आरसीसी यानी रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस के संचालक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। उसके मोबाइल फोन से नीट के लीक प्रश्नपत्र बरामद हुए हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपी एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य था, जो प्रश्नपत्र लीक करता था। इससे पहले सीबीआई ने जांच में पेपर लीक का मास्टरमाइंड पी।वी। कुलकर्णी को माना है और और ये नेटवर्क बायोलॉजी की सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मांधरे, ब्यूटीशियन मनीषा वाघमारे, शुभम खैरनार, एक छात्र यश यादव और धनंजय लोखंडे से होकर बिंबाल परिवार तक जाता है। इसमें मांगीलाल बिंबाल, दिनेश बिंबाल और विकास बिंबाल शामिल है।

इस पूरे नेटवर्क की पहली कड़ी शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर हैं। इसके बाद सीबीआई की जांच सबसे अहम पहलू की ओर मुड़ गई है, जहां उसका शक किसी एनटीए स्टाफ के ऊपर ही है, क्योंकि बिना हज़्र स्टाफ के



मिलीभगत के ये लीक संभव नहीं हो सकता है, सीबीआई ऐसा मान रही है। उधर, सीबीआई इन सभी से पूछताछ कर रही है। एनटीए के नीट पेपर लीक मामले में इन सभी की क्या-क्या भूमिका थी, इन सब पर डालते हैं एक नजर।

शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर

सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से आरसीसी रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस के संचालक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया है। मोटेगांवकर के फोन से नीटके पेपर बरामद हुए हैं। अभी तक मोटेगांवकर पहली कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। जिसने लीक पेपर को नेटवर्क को फैलाया। सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी ने शिवराज मोटेगांवकर से 8 से 10 घंटे तक लंबी पूछताछ की है। इसमें हज़्र से जुड़े कई अधिकारियों के साथ संपर्कों और पेपर लीक के मास्टरमाइंड पी।वी। कुलकर्णी से रिश्तों को लेकर सवाल पूछे गए हैं।

पीवी कुलकर्णी-केमेस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर

पेपर लीक मामले में दावा नाम पीवी कुलकर्णी का है। छद्म का दावा है कि केमिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर पी।वी। कुलकर्णी उस एक्सपर्ट टीम का हिस्सा थे जो प्रश्नपत्र को तैयार करने की प्रक्रिया करते थे। यानी पेपर

लीक मामले में सीधे तौर पर पेपर तैयार करने वालों की ही भूमिका नजर आ रही है।

मनीषा गुरुनाथ मांधरे- बायोलॉजी टीचर

सीबीआई ने इस मामले में बायोलॉजी की सीनियर टीचर मनीषा गुरुनाथ मांधरे को भी गिरफ्तार किया है। मनीषा मांधरे भी पेपर तैयार करने वाली एक्सपर्ट टीम में शामिल थीं। इन्होंने ही एनटीए से प्रश्नपत्र चुराए थे। केमेस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न लीक होने के बाद सवाल है कि फिजिक्स का एक्सपर्ट कौन था क्योंकि फिजिक्स के भी कुछ सवाल लीक होने के संकेत मिले हैं। इस मामले में एक और संदिग्ध की पहचान की गई है। हालांकि सीबीआई ने अभी उसका खुलासा नहीं किया है।

विवेक पाटिल को शिवराज ने लीक पेपर की कॉपी दी

सामने आया था कि हृदयश्चक्र परीक्षा में इस्तेमाल किए गए प्रश्नपत्र और रिजर्व सेट के बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवाल एक ही क्रेश्चन बैंक से मेल खाते हैं। यही क्रेश्चन बैंक छद्म जांच का बड़ा आधार बना है। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक, शिवराज मोटेगांवकर ने लीक प्रश्नपत्र और उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपी विवेक पाटिल समेत कई लोगों को उपलब्ध कराई थी। एजेंसी को आरोपी के मोबाइल फोन में लीक प्रश्नपत्रों का वीडियो भी मिला है। जांच एजेंसी को मोटेगांवकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट और उसके घर पर तलाशी में केमिस्ट्री का क्रेश्चन बैंक मिला। इसमें ठीक वही सवाल मौजूद थे, जो 3 मई को आयोजित हृदयश्चक्र-त 2026 परीक्षा में पूछे गए थे। इस बरामदगी को जांच में बेहद अहम माना जा रहा है।

स्टेल प्रमुख समाचार

बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में किया सुपड़ा साफ

सिलहट(बांग्लादेश)। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचते हुए पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में 78 रन से हराकर दो मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान ने आखिरी दिन संघर्ष जर्जर किया, लेकिन टीम रिकॉर्ड रन चेज पूरा करने में नाकाम रही।

मोहम्मद रिजवान ने एक छोर संभालते हुए शानदार 94 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन वह टीम को ऐतिहासिक जीत नहीं दिला सके। रिजवान के आउट होते ही पाकिस्तान की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो गई और बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया।

437 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने पांचवें दिन 316/7 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। शुरुआत में रिजवान को जीवनदान भी मिला, जब मेहदी हसन मिरजान ने उनका कैच छोड़ दिया। इसके बाद रिजवान और साजिद खान ने तेज बल्लेबाजी करते हुए आठवें विकेट के लिए 50 रन जोड़े।

साजिद खान 28 रन बनाकर ताइजुल इस्लाम का शिकार बने। इसके बाद रिजवान अकेले लड़ते रहे, लेकिन शोरीफुल इस्लाम की गेंद पर आउट होकर शतक से सिर्फ 6 रन दूर रह गए। उन्होंने 166 गेंदों में 94 रन बनाए। आखिर में ताइजुल ने खुर्रम शहजाद का विकेट लेकर बांग्लादेश को 78 रन की शानदार जीत दिलाई।

बांग्लादेश की जीत के सबसे बड़े हीरो लेफ्ट आर्म स्पिनर ताइजुल इस्लाम रहे। उन्होंने दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर पाकिस्तान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। ताइजुल ने मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए लगातार दबाव बनाए रखा और अहम मौकों पर विकेट निकाले।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/प्रमुख समाचार

प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 117 अंक चढ़ा निफ्टी 23,659 पर बंद

मुंबई। भारतीय शेयर बाजार बुधवार (20 मई) को उतार-चढ़ाव के बाद बढ़त के साथ बंद हुआ। दिनभर की गिरावट को पीछे छोड़ते हुए बाजार ने आखिरी एक घंटे में मजबूत रिकवरी दिखाई। इस तेजी में कई बड़े शेयरों का अहम योगदान रहा। बीएसई सेंसेक्स 117.54 अंक या 0.16 प्रतिशत की बढ़त के साथ 75,318.39 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 75,406.18 का उच्च स्तर और 74,529.41 का निचला स्तर छुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 50 भी मजबूती के साथ 41 अंक या 0.17 प्रतिशत की बढ़त लेकर 23,659 पर बंद हुआ। दिन के दौरान निफ्टी ने 23,690.90 का उच्च और 23,397.30 का निचला स्तर बनाया। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंडालको इंडस्ट्रीज और बजाज ऑटो जैसे बड़े शेयर शामिल रहे। इन दिग्गज कंपनियों में खरीदारी ने बाजार को सपोर्ट दिया।

जयंतीलाल भंडारी

इस समय जब पश्चिम एशिया संकट के कारण नियतों में कमी, महंगाई और आयात लागत में वृद्धि से देश की विकास दर में गिरावट आ रही है, तब भारत तेजी से व्यापार समझौते और उनके लाभप्रद क्रियान्वयन के लिए नए सरल श्रम कानूनों के क्रियान्वयन की राह पर आगे बढ़ रहा है।

हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी ने पांच देशों-संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की आदरलैंग्य के दौरान इन देशों के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौते किए हैं। साथ ही, हाल ही में केंद्र सरकार ने गण्ट अधिसूचना के जरिये पूरे देश में चार नई श्रम संहिताएं लागू करके घटती हुई विकास दर को थामने तथा विकास की नई संभावनाओं को आकार देने का मार्ग प्रशस्त किया है। ये नई श्रम संहिताएं सार्वभौमिक सामाजिक

सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मजदूरी का भुगतान, सुरक्षित कार्यस्थल और नारी व युवा शक्ति के लिए लाभकारी अवसरों के लिए एक मजबूत नींव के रूप में काम करेंगी। साथ ही, भविष्य के लिए एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करेंगी, जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को मजबूत बनाएगा। इन संहिताओं से देश सेवा क्षेत्र के साथ-साथ विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशियाई संकट का दुनिया के साथ-साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने लगा है। ऐसे में, नए श्रम कानून देश की विकास दर बढ़ाने, देश में विदेशी निवेश के प्रवाह को आकर्षित करने तथा द्विपक्षीय व मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के माध्यम से निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की एक

यूएन ने घटाया भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान

वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने साल 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है। पहले यह अनुमान 6.6 प्रतिशत था। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी वजह पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुई वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक झटकों को बताया है। हालांकि यूएन के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिम एशिया संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक और बड़ा झटका दिया है, जिससे आर्थिक वृद्धि धीमी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अब भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में रहेगा और 2026 में उसकी अर्थव्यवस्था 6.4% की दर से बढ़ सकती है।



हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिम एशियाई संकट के चलते चालू वित्त वर्ष (2026-27 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 0.6 प्रतिशत गिरकर 6.3 प्रतिशत रह जाएगी। ऐसे में, नए श्रम कानूनों की मदद से भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य में आगे बढ़ने और विकास करने की उम्मीद दिखाई दे रही है। नए श्रम कानूनों से वैश्विक चुनौतियों के बीच दुनिया में भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बना रह सकता है। इसकी पुष्टि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की रिपोर्ट 2026 भी करती है,

टाटा पावर की ईवी इकाई ने खोले अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग स्टेशन

नईदिल्ली। टाटा पावर की इकाई टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अल्ट्रा-फास्ट ईवी चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार किया है। कंपनी ने बुधवार को बयान में कहा कि इस सहयोग के तहत टाटा पावर ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड (टीपीईवीसीएसएल) ने एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड पर 63वें और 69वें ‘माइलस्टोन’ पर अल्ट्रा-फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। एक्सप्रेसवे पर अपने विस्तार के तहत टीपीईवीसीएसएल ने दिल्ली से यात्रा करने वाले वाहनों के लिए 63वें ‘माइलस्टोन’ पर चार चार्जिंग गन के साथ 240 किलोवाट का अल्ट्रा-फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है। कंपनी ने 69वें ‘माइलस्टोन’ पर एक और ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है ताकि दोनों दिशाओं में आने-जाने वाले यात्रियों को चार्जिंग की सुविधा मिल सके।

23 से 28 मई तक बंद रहेगी एसबीआई बैंकिंग सेवाएं

नईदिल्ली। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। यदि आप बैंक शाखा से जुड़े कोई जरूरी कार्य जैसे नकद लेन-देन, चेक क्लियरेंस या लोन संबंधी कागजी प्रक्रिया निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो उसे समय रहते पूरा कर लेना उचित होगा। सूत्रों के अनुसार, 23 मई (शनिवार) से 28 मई (गुरुवार) तक लगातार 6 दिनों के लिए एसबीआई शाखाओं में कार्य प्रभावित रह सकता है। 23 मई महीने का चौथा शनिवार होने के कारण संस्कार अवकाश, 24 मई रविवार के चलते साप्ताहिक अवकाश, 25-26 मई को कर्मचारी यूनियन द्वारा प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल, 27-28 मई को ईद-उल-अजहा के अवसर पर कई राज्यों में अवकाश रहेगा।

भारत तेजी से व्यापार समझौते और उनके लाभप्रद क्रियान्वयन की राह पर आगे बढ़ रहा

जिसके अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच 2026 में 6.5 प्रतिशत विकास दर के साथ भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती विकास दर वाला देश बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) और विश्व बैंक ने भी भारत के लिए ऐसे ही तेज विकास दर के अनुमान पेश किए हैं। अब देश में देशी-विदेशी निवेश बढ़ने की संभावनाएं बढ़ेंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने के कारण दुनिया के विकसित और विकासशील देश भारत के साथ व्यापार बढ़ाने में ज्यादा रुचि दिखा सकते हैं।

यह कोई छोटी बात नहीं है कि अब दुनियाभर के देशों का मानना है कि अगर वे आर्थिक रूप से तेजी से बढ़ते हुए भारत के साथ नहीं जुड़ पाए, तो वे महत्वपूर्ण मौका गंवा देंगे। ऐसे में, नए श्रम कानून भारत के लिए व्यापार समझौतों से लाभ के मद्देनजर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। भारत के लिए एफटीए और द्विपक्षीय व्यापार

समझौतों के जरिये निर्यात के नए बाजारों में दस्तक देने की संभावनाएं तेज होंगी। नए श्रम कानूनों से सेवा निर्यात में भी वृद्धि होते हुए दिखाई देगी। आईएमएफ की नई विश्व आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ दशकों में भारत से सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं के निर्यात की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ा है। साथ ही, एआई, डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्लाउड कंप्यूटिंग और रिमोट वर्क ने कई सेवाओं को व्यापार योग्य बना दिया है। इसी का परिणाम है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सेवाओं का निर्यात रिकॉर्ड 387.5 अरब डॉलर तक जा पहुंचा, जो 13.6 फीसदी की वृद्धि है। उम्मीद है कि नए श्रम कानूनों से रोजगार व्यवस्था बेहतर होगी, उद्योग आधुनिक बनेंगे, श्रमिक हित का खयाल रखा जाएगा और जरूरतों के अनुसार श्रम व्यवस्था मजबूत होगी। इससे भारत तेज विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकेगा।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में गृह मंत्री शर्मा ने 54 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहनों को दिखाई हरी झंडी

डायल-112 सेवा का विस्तार 33 जिलों में: शर्मा

रायपुर। राजधानी रायपुर में नागरिक सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं तकनीक आधारित बनाने की दिशा में आज रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में डायल-112 फेस-2 नेक्स्ट जनरेशन सेवा का भव्य शुभारंभ उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर 54 नवीन इमरजेंसी रिस्पॉन्स वाहनों को शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर रायपुर (पश्चिम) विधायक राजेश मूणत, रायपुर (उत्तर) विधायक पुरंदर मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित कांबले, कलेक्टर रायपुर शौरव कुमार, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता सिन्हा सहित शासन एवं प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

उपमुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व में



डायल-112 सेवा केवल 16 जिलों तक सीमित थी, जिसे अब विस्तारित कर प्रदेश के सभी 33 जिलों में लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र हेतु 33 ईआरवी एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु 21 ईआरवी सहित कुल 54 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर त्वरित सहायता उपलब्ध कराने हेतु 4 विशेष हाईवे पेट्रोलिंग वाहन भी तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी वाहन अत्याधुनिक जीपीएस सिस्टम, स्मार्ट कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सिस्टम, कॉल रिकॉर्डिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग एवं डिजिटल कम्युनिकेशन तकनीक से लैस

हैं, जिससे सूचना प्राप्त होते ही त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी। डायल-112 सेवा के माध्यम से पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम राष्ट्रीय मानक के अनुरूप रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गृह मंत्री ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना में तकनीकी एवं रणनीतिक सहयोग प्रदान करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

डायल-112 सेवा एक नंबर- सबकी भी आकस्मिक, आपातकालीन अथवा संकट की स्थिति में बिना किसी संकोच के तत्काल डायल-112 सेवा का उपयोग करें। रायपुर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा, सहायता एवं त्वरित सेवा हेतु चौबीसों घंटे प्रतिबद्ध एवं तत्पर है।

कर पुलिस सहायता, फायर ब्रिगेड, मेडिकल इमरजेंसी, महिला हेल्पलाइन (1091), चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), आपदा प्रबंधन एवं हाईवे इमरजेंसी जैसी समस्त आपातकालीन सेवाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री राजेश मूणत जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ आज तेजी से सुरक्षित एवं नक्सल मुक्त राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है तथा डायल-112 का नेक्स्ट जनरेशन मॉडल प्रदेश की आपातकालीन सेवाओं को और अधिक मजबूत एवं सक्षम बनाएगा।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट की अपील

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी आकस्मिक, आपातकालीन अथवा संकट की स्थिति में बिना किसी संकोच के तत्काल डायल-112 सेवा का उपयोग करें। रायपुर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा, सहायता एवं त्वरित सेवा हेतु चौबीसों घंटे प्रतिबद्ध एवं तत्पर है।

बस्तर पर अमित शाह का बयान सिर्फ झूठ का पुलिंदा: भूपेश बघेल

■ आदिवसियों को गाय देने की घोषणा एक बार फिर ठगने की कोशिश - डॉ. महंत



रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने राजीव भवन में संयुक्त पत्रकार वार्ता को सम्बोधित किया।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा की है, हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं। सभी को करना चाहिए। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक में और उसके बाद अमित शाह जी ने जो कुछ कहा वह सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। स्पष्ट दिखाता है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने अमित शाह को

बस्तर के बारे में झूठी जानकारी दी है जिससे वे भ्रमित हो गए।

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह सच्चाई से मुंह मोड़ रहे। सच यह है कि 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस की सरकार ने बस्तर में नक्सली उन्मूलन की दिशा में ठोस कार्य किया और उसी के दम पर वर्तमान सरकार सफलता पूर्वक नक्सली अभियान चला पाई। अमित शाह जी ने खुद जाकर बस्तर के एक कैप का औचक निरीक्षण किया था और देखा था कि किस तरह कैप में बिजली, राशन की दुकान, खेल का मैदान आदि काम कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से बात भी की थी और

संतुष्ट होकर लौटे थे। सच यह है 2022 में खुद अमित शाह ने माना था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सली घटनाओं में बहुत प्रतिशत की कमी आई है।

सच यह है कि अमित शाह जी ने 2022 की क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद कहा था, “वामपंथी उग्रवाद की समस्या अब छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। जब 2009 में वामपंथी उग्रवादी हिंसा चरम पर थी तब वामपंथी उग्रवादी हिंसक घटनाओं की संख्या 2258 थी जो 2021 में घटकर 509 हो गई। उन्होंने कहा कि 2019 से वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में बहुत तेजी से कमी आई है। 2

यातायात सुरक्षित सुत्यवस्थित बनाने ई-रिवशा पंजीयन अभियान शुरू



रायपुर। शहर में यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के उद्देश्य से रायपुर पुलिस ने ई-रिवशा पंजीयन अभियान की शुरुआत कर दी है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के नेतृत्व में बुधवार को इस विशेष अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 20 मई से 5 जून 2026 तक कुल 15 दिनों तक चलाया जाएगा। कमिश्नरेट रायपुर पुलिस द्वारा जनहित फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किए गए

ऑनलाइन पंजीयन लिंक और क्यूआर कोड सिस्टम के माध्यम से शहर में संचालित सभी ई-रिवशा और ऑटो चालकों का अनिवार्य पंजीयन किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में ई-रिवशा संचालन को व्यवस्थित करना और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

पुलिस विभाग ने बताया कि अब प्रत्येक ई-रिवशा चालक को क्यूआर कोड स्कैन कर ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीयन कराना

होगा। पंजीयन प्रक्रिया के दौरान चालक को अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन नंबर और आरसी संबंधी जानकारी अपलोड करनी होगी। इससे सभी ई-रिवशा और चालकों का डाटा रायपुर पुलिस के पास सुरक्षित रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से शहर में संचालित ई-रिवशा वाहनों की वास्तविक संख्या का पता लगाया जा सकेगा। साथ ही किसी भी कानून व्यवस्था या आपराधिक मामले में संबंधित वाहन और चालक की तुरंत पहचान कर कार्रवाई करना आसान होगा। पुलिस के अनुसार इस पंजीयन व्यवस्था से यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। यदि किसी यात्री का सामान ई-रिवशा में छूट जाता है, तो वाहन और चालक की जानकारी उपलब्ध होने से तत्काल संपर्क कर सामान वापस दिलाने में सहायता मिलेगी।

पेयजल की नियमित जलापूर्ति और शुद्धता की जांच जरूरी: मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में नियमित जलापूर्ति और पेयजल की शुद्धता की निरंतर जांच कराने के कड़े निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज यहाँ मंत्रालय (महानदी भवन) में श्राज्य जल एवं स्वच्छता मिशनश् की अपेक्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई।

बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 के क्रियान्वयन की कार्ययोजना, पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था, आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण, जनभागीदारी, जल संरक्षण तथा रसुजलम भारतश् डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही, भू-जल के विवेकपूर्ण उपयोग और

जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए एजल अर्पणश् की नई पहल पर भी विचार-विमर्श किया गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न गांवों और बसाहटों में पानी की टँकियां तथा नल लगाने का काम पूरा होने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नियमित जलापूर्ति और पानी की गुणवत्ता बनाए रखना है।

ग्राम पंचायतों को नल-जल योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए गठित समितियों में महिलाओं की भागीदारी को अनिवार्य किया गया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर सहयोग करने के निर्देश दिए। नल-जल योजनाओं की निरंतर और प्रभावी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सीधे जिला कलेक्टरों की होगी।



■ समन्वय साहित्य परिवार का बृहद साहित्यकार सम्मेलन सम्पन्न

रायपुर। छत्तीसगढ़ी भाषा के गद्य जगत के युग प्रवर्तक डॉ. पालेश्वर शर्मा की 98 वीं जयंती पर बृहद साहित्यकार सम्मेलन का आयोजन किया गया।

ऋषि- कृषि संस्कृति के उपासक,भाषाविद् डॉ.पालेश्वर की स्मृति में पहला छत्तीसगढ़ी गद्य साहित्य सम्मान विजय मिश्रा %अमित% को दिया गया। उनकी पचास वर्षीय साहित्य साधना का मूल्यांकन करते हुए समन्वय साहित्य परिवार के प्रबुद्ध निर्णायक मंडल ने विजय मिश्रा का चयन किया।पुरस्कार के अंतर्गत सम्मान राशि 5001/ रुपए के साथ ही प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह एवं शाल- श्रीफल से उन्हें सम्मानित किया गया।



सम्मेलन में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा,अध्यक्ष डॉ. चित रंजन कर,रविशंकर विश्वविद्यालय के साहित्य भाषा अध्ययन शाला के पूर्व अध्यक्ष तथा विशिष्ट अतिथि की आसंदी से छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव दिनेश मिश्रा, पाणिनीय शोध संस्थान की अध्यक्ष डॉ.पुष्पा दीक्षित, पूर्व विधायक चंद्रप्रकाश वाजपेई, दिवूपी

लेखिका सरला शर्मा एवं प्रख्यात नवगीतकार डॉ अजय पाठक शामिल हुए।

संस्था के प्रेक्षाध्यक्ष डॉ देवधर महंत ने डॉ पालेश्वर शर्मा के व्यक्तित्व कृतित्व पर प्रकाश डाला। अतिथियों ने कीर्तिशेष डॉ शर्मा की रचनाओं को कालजयी और नवपीढ़ी के लिए पथ-प्रदर्शक निरूपित किया।आभार प्रदर्शन संस्था के केंद्राध्यक्ष डॉ गंगाधर पटेल ने किया।

‘गिफ्ट तिलापिया की वैज्ञानिक खेती’ पर चिंतन शिविर आज

रायपुर। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में 21 मई को राजधानी रायपुर के व्हीआईपी रोड स्थित होटल बेबीलॉन में 10 बजे से एक दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का उद्घाटन कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम द्वारा किया जाएगा। गिफ्ट तिलापिया की वैज्ञानिक खेती विषय पर केंद्रित इस शिविर में राज्य के अंतर्देशीय जल संसाधनों को निर्यात की वैश्विक श्रृंखला से जोड़ने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। कलस्टर्स में से छत्तीसगढ़ को देश के एकमात्र तिलापिया कलस्टर के रूप में पहचान मिली है। वर्ष 2025-26 में भारत का समुद्री उत्पाद निर्यात 72 हजार 325.82 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसे और गति देने के लिए अब तिलापिया जैसी प्रजातियों की वैज्ञानिक खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ उपस्थित रहकर राज्य में मछली पालन की उत्पादन क्षमता और निर्यात की संभावनाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

छत्तीसगढ़ बना कृषि सुधारों का राष्ट्रीय मॉडल: मंत्री नेताम

रायपुर। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 19 मई को आयोजित राष्ट्रीय जोनल कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ को कृषि नवाचार, किसान कल्याण और टिकाऊ खेती के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों की आय वृद्धि, कृषि विविधीकरण और ग्रामीण समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है।

केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने तिलहन मिशन के तहत पूर्वोत्तर पांच राज्यों में छत्तीसगढ़ द्वारा लक्ष्य पूरा करने में पहले स्थान प्राप्त करने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्य में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में धान के लिए सबसे पारदर्शी और ऐतिहासिक समर्थन व्यवस्था मानी जा रही है। पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने 437 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी कर किसानों के खातों में लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये का सीधा भुगतान किया है। भूमिहीन मजदूरों से लेकर डिजिटल खेती तक, छत्तीसगढ़ का व्यापक कृषि विजन: सम्मेलन में मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार केवल बड़े किसानों तक सीमित नहीं है।



रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में धान के लिए सबसे पारदर्शी और ऐतिहासिक समर्थन व्यवस्था मानी जा रही है। पिछले तीन वर्षों में राज्य सरकार ने 437 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी कर किसानों के खातों में लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपये का सीधा भुगतान किया है। भूमिहीन मजदूरों से लेकर डिजिटल खेती तक, छत्तीसगढ़ का व्यापक कृषि विजन: सम्मेलन में मंत्री श्री नेताम ने कहा कि राज्य सरकार केवल बड़े किसानों तक सीमित नहीं है।

29 से 31 मई तक होगा तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 29, 30 एवं 31 मई को कृषि महाविद्यालय परिसर रायपुर में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 250 से अधिक देशी एवं विदेशी किस्मों का प्रदर्शन किया जायेगा। इस कार्यक्रम में आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसमें छत्तीसगढ़ एवं देश के विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। इस अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रतियोगिता भी आयोजित है। आम की सजावट प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है जिसमें विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिलाएं तथा अन्य सामान्यजन भी पंजीयन कर भागीदारी कर सकते हैं। आम महोत्सव में पंजीयन एवं प्रवेश पूर्णतया निःशुल्क है। इस आयोजन में संस्थागत एवं व्यक्तिगत प्रतियोगी भी सहभागी हो सकते हैं।कृषि विश्वविद्यालय में 29 से 31 मई तक होगा तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सवआम महोत्सव के प्रथम दिवस 29 मई को प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक प्रविष्टियों का पंजीयन किया जाएगा। सामान्यजनों के अवलोकनार्थ यह प्रदर्शनी तीनों दिन रात्रि 9 बजे तक खुली रहेगी।

नगं चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरेगी आम आदमी पार्टी

रायपुर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ ने प्रदेश में होने वाले आगामी नगर पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनावों के लिए अपने प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह इन चुनावों को पूरी गंभीरता, संगठनात्मक मजबूती और जनता के मुद्दों के साथ लड़ेगी।दिल्ली के विधायक एवं आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के सहप्रभारी माननीय मुकेश अहलावत जी के निर्देशानुसार प्रदेश पदाधिकारियों के साथ विस्तृत मंथन, स्थानीय समीकरणों, जनस्वीकृति एवं संगठनात्मक फीडबैक के आधार पर प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है। पार्टी द्वारा बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 29 से साहिल खान तथा जगदलपुर नगर निगम वार्ड क्रमांक 16 से रुबीना कुँश्री को अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है।इसी प्रकार नगर पंचायत घुमका से अध्यक्ष पद हेतु अलीशा जोशी को प्रत्याशी बनाया गया है। वार्ड प्रत्याशियों में आशुतोष नारायण सिंह, रेवती बघेल, हुमान लाल जोशी, रविन्द्र ठाकुर, विक्रम वर्मा, गोपेश्वर वर्मा, हिंसा राम वर्मा, पदमा वर्मा, दिनेश्वरी साहू, जयप्रकाश यदु, रोशन कुमार, केलेश्वरी वर्मा, पूर्णिमा वर्मा, कमली बाई वर्मा एवं सालिक राम को पार्टी ने मैदान में उतारा है।नगर पंचायत बन्हीडीह से अध्यक्ष पद हेतु माधव प्रसाद डडसेना को प्रत्याशी घोषित किया गया है।

23 से पहले निपटा ले एसबीआई बैंक के ग्राहक अपना काम

रायपुर। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के ग्राहक बैंक से संबंधित जो भी कार्य है वही 23 मई से पहले कर लें नहीं तो उन्हें पूरे 6 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इस मुख्य कारण यह है कि 23 मई को महीने का चौथा शनिवार (आधिकारिक अवकाश), 24 मई रविवार (साप्ताहिक अवकाश), 25 और 26 मई को एसबीआई कर्मचारी यूनियन देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ की भी 400 से अधिक शाखाओं के 2100 से अधिक कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। 27 और 28 मई को बकरीद (ईद-उल-अजहा) के चलते कई राज्यों में सरकारी छुट्टी रहेगी। इस दौरान एटीएम व इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं चालू रहेंगी और एसबीआई की शाखाएं शुक्रवार, 29 मई को दोबारा खुलेंगी। ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉफ फेडरेशन (एमपी सीजी में वर्कमेन यूनियन के नाम से जाना जाता है) ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 25 और 26 मई को दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियन का आरोप है कि बैंक मैनेजमेंट कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े कई फैसले उनकी सहमति या बिना सलाह के लागू कर रहा है, जिससे कर्मचारियों में भारी असंतोष है। यूनियन ने मैनेजमेंट के सामने 16 मुख्य मांगें रखी हैं। इनमें ये सपोर्ट स्टॉफ और मेसेंजर्स की भर्ती की मांग प्रमुख है। 20-22 वर्ष से मैसेंजर की और 7-8 वर्ष से सुरक्षा गार्डों की भर्ती नहीं की जा रही है।

साय सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर सुशासन तिहार मना रही जनता

रायपुर। सुशासन त्योहार के आते ही छत्तीसगढ़वासियों की नई ऊर्जा मिली। नई सरकारी स्कीमों का लाभ के साथ साय सरकार ने प्रदेश की जनता के हित में एक और तिहार मनाने का आह्वान किया है, वो है सुशासन तिहार सुशासन तिहार 2026 जिसके तहत राज्य सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को सीधे उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना और सरकारी सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाना है। जिलों में लगाए जा रहे शिविरों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक बड़ी संख्या में योजनाओं से जुड़ रहे हैं।

स्वास्थ्य, राशन कार्ड, पेंशन, आवास और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ तत्काल दिया जा रहा है। कई जिलों में हजारों लोगों ने शिविरों में पहुंचकर अपने आवेदन

जमा किए और मौके पर ही समाधान प्राप्त किया। सरकार का कहना है कि इस पहल से लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने की परेशानी से राहत मिल रही है और प्रशासन सीधे जनता के द्वार तक पहुंच रहा है। सुशासन तिहार के जरिए प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आम जनता को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके।

गरियाबंद जिला विकासखंड फिंगेश्वर के ग्राम पोखरा में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में कृषक संतोष साहू को केसीसी सह पासबुक प्रदान किया गया। केसीसी सह पासबुक मिलने से किसानों को जौरो प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। जिससे वे खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं अन्य कृषि आदानों की व्यवस्था आसानी से कर सकेंगे। साथ ही धान विक्रय से



संबंधित राशि का भुगतान एवं बैंकिंग लेन-देन भी अधिक सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ हो सकेगा।किसान संतोष साहू ने केसीसी सह पासबुक प्राप्त होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शासन की किसान हितैषी योजनाओं से किसानों को बड़ी राहत

मिल रही है तथा अब खेती कार्य और अधिक सुगमता से किया जा सकेगा। सुशासन तिहार के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुंचाया जा रहा है।

3 महिला समूहों को मिला 10 लाख रुपये का ऋण सुकमा जिले के ग्राम पंचायत ढोंढरा में सुशासन तिहार के तहत आयोजित विशेष शिविर में ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ मौके पर उपलब्ध कराया गया। शिविर में प्रशासन की सक्रियता और जनसेवा का प्रभावी स्वरूप देखने को मिला। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत तीन महिला स्व-सहायता समूहों को कुल 10 लाख रुपये का बैंक ऋण वितरित किया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए राजेश्वरी समूह को 4 लाख रुपये, सीताफल समूह को 3 लाख रुपये तथा

कनकादुर्गा समूह को 3 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। इस पहल से महिलाओं के स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी।

आवेदन के साथ ही हुआ त्वरित निराकरण सरगुजा जिले के ग्राम बड़ादमली निवासी फूल मंतिया सिंह को सुशासन तिहार में आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराया गया, जिससे उनके परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा का मजबूत संबल मिला है। फूल मंतिया सिंह ने बताया कि वे लंबे समय से आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रयासरत थीं, लेकिन विभिन्न कारणों से उनका कार्ड नहीं बन पा रहा था। गांव में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अधिकारियों ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके पर ही उनका आयुष्मान कार्ड बनाकर सौंप दिया।

5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की

सुविधा आयुष्मान कार्ड प्राप्त होने पर सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि अब उनके परिवार को गंभीर बीमारी की स्थिति में 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। इससे आकस्मिक चिकित्सा खर्च की चिंता काफी हद तक समाप्त हो गई है। फूल मंतिया सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से गांव में भी समस्याओं का समाधान हो रहा है और गरीब परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ सहजता से मिल रहा है।

सुशासन तिहार ने लौटाई मुस्कान जनपद पंचायत मरवाही अंतर्गत ग्राम पंचायत कटरा निवासी दिव्यांग हितग्राही स्वरूप सिंह पोतें के जीवन में भी सुशासन तिहार नई उम्मीद और राहत लेकर आया है। स्वरूप सिंह पोतें 80 प्रतिशत अस्थि बाधित दिव्यांग हैं।